अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजाित्यों का शैक्षिक विकास

सस्थिति और कार्यक्रम

भारत सरकार मानव संसाधन विकास मंत्रालय शिक्षा विभाग आयोजना, मानिटरिंग और शैक्षिक प्रभाग (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ) नई दिल्ली 1995

आमुख

अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां शैक्षिक विकास की दृष्टि से भारतीय समाज के सर्वाधिक पिछड़े वर्ग हैं। वे समाज के वैधानिक रूप से मान्य कमजोर वर्ग हैं और उन्हें आयोजना की मौजूरा पद्गति के अंतर्गत एक विशेष लक्षित समूह बनाया गया है।

स्वतन्त्रता प्राप्त के पश्चात अपनाई गई सकारात्मक नीतियों के कारण मारत ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के श्लीक्षक विकास में महत्वपूर्ण प्रगति की है। प्राइमरी स्तर पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के नामांकन में पर्याप्त वृद्धि हुई है, प्राथमिक शिक्षा में उनकी सहभागिता जनसंख्या में कमोबेशी उनकी संख्या के अनुपात में है। परन्तु स्कूल बीच में छोड़ने वाले बच्चों की संख्या अभी मी अधिक है। क्षेत्रीय और बालक-बालिका संबंधी उल्लेखनीय असमानताएं व्याप्त हैं। सरकार इस अन्तर को कम करने के प्रयास कर रही है। शिक्षा के समी कार्यक्रमों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों पर विशेष ध्यान दिया जाता है।

इस प्रकाशन में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक विकास की सांख्यिकी-रूपरेखा के साथ-साथ केन्द्रीय स्तर पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक उन्धान के लिए सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों का सार प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। सुधार संबंधी सुझावों का स्वागन है ताकि वर्तमान प्रकाशन की अपेक्षा आने वाले संस्करण बेहतर हो सकें। आशा है कि यह प्रकाशन उन लोगों के लिए लाभदायक होगा जिन्हें वंचित क्षेत्रों के शैक्षिक पहलुओं का अध्ययन करने में रुचि है।

में मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग), कल्याण मंत्रालय, श्रम मंत्रालय और स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय से सम्बद सभी ब्यूरो तथा संगठनों को धन्यवाद देना चाहुंगा जिन्होंने इस प्रकाशन के लिए सुसंगत सूचना देकर सहयोग प्रदान किया है।

मैं इस प्रकाशन को निकालने में अनु० जाति/अनु० जनजाति प्रकोप्ठ के स्टाफ द्वारा किये गये प्रयासों की मी सराहना करता है।

> (डा. आर. वी. वैद्यनाथ अय्यर) संयुक्त सचिव भारत सरकार मानव संसाधन विकास मंत्रालय शिक्षा विभाग नई दिल्ली

दिनांक: 25 अक्तूबर, 1995

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ का परियोजना स्टाफ

श्री मंगत सिंह : उप सचिव

श्री टी० सी० जेम्स : अवर सचिव

श्री चन्द्रकांत : सहायक निदेशक

श्रीमती उमा गर्ग : वरिष्ठ अन्वेषक

श्री यू० एस० राजपूत : वरिष्ठ अन्वेषक

विषय सूची

क्रम	सं ० विषय	पृष्ठ सं
	पस्तावना	(v)
I.	शैक्षिक स्थिति : सिंहावलोकन	
	 जनसंख्या रूपरेखा 	(1)
	2. साक्षरता स्तर	1
	3. स्कूल नामांकन	2
	4. पदाई स्रोहने वालों की दर	3
11.	नीति निर्धारण	
	1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति (स॰ शि॰ नी॰-1986)	4
	2. राष्ट्रीय प्राक्षा नीति, 1986 की कार्य योजना, 1992	5
111	कार्यक्रम	,
	क. शिक्षा विभाग	6
	(i) प्रारंभिक शिक्षा	6
	(ii) माध्यमिक शिक्षा	8
	(iii) विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा	10
	(iv) तकनीकी शिक्षा	10
	(v) प्रोद शिक्षा	13
	(vi) महिलाओं के अधिकार	14
	(vii) छात्रवृत्तियां	14
	(viii) भाषायें	14
	(ix) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंघान एवं प्रशिक्षण परिषद	
	(x) राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना एवं प्रशासन संस्थान	17
	(xi) अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना तथा जनजातीय उपयोजना	17
	(xii) शैक्षिक संस्थाओं में किए जाने वाले दाखिलों तथा नियुक्तियों में आरक्षण खा. कल्याण मंत्रालय	18
		20
	(i) मैटिक-पूर्व छात्रवृत्तियां	20
	(ii) उत्तर-मैटिक छाज्रवृत्तियां	20
	(iii) राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्तियां	21
	(iv) सात्रावास	22
	— अनुसूचित जातियों के लिए महिला छात्रावास	22
	— अनुसूचित जातियों के लिए पुरुष छात्राया स	22
	— अनुसूचित जनजातियों के लिए महिला खात्रावास — अनुसूचित बन्नानियों के लिए प्रकार कार्यावास	23
	— अनुसूचित जनजातियों के लिए पुरुष खात्रावास (v) पुस्तक बैंक	23
	(v) युस्तक बाक (vi) कोचिंग और सम्बद योजना	
	(४१) कमचन आर सम्बद्ध थीजनी	23

	पृष्ठ संख्या
(vii) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के छात्रों की योग्यता को बढाना	23
(viii) स्वैन्छिक संगठनों को सहायता	23
(ix) अनुसंघान और प्रशिक्षण	24
(x) टी०एस०पी० क्षेत्रों में आग्रम स्कूल	24
(xi) डॉक्टरल और उत्तर डॉक्टरल शिक्षावृत्तियां प्रदान करना	24
(xii) कम साक्षरता वाले क्षेत्रों में आदिवासी लड़कियों की शिक्षा	24
(xiii) अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना के लिये विशेष केन्द्रोय सहायता	24
ग. अन्य विभाग	24
घ. राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन	24
संलग्नक .	
(i) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या. 1991	27
(ii) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की साक्षरता दर, 1991	28
(iii) विभिन्न स्तरों पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का नामांकन (1993-94)	29
(iv) पदाई बीच में छोड़ने वाले अनुसूचित जाति के छात्रों की दर (1989-90)	30
(v) पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले अनुसूचित जनजातियों के छात्रों की दर (1989-90)	31
(vi) नवोदय विद्यालयों में 31-3-1994 की स्थिति के अनुसार खात्रों का नामांकन	33
(vii) वर्ष 1994-95 के दौरान दी गई एन टी एस छात्रवृत्तियों की संख्या	34
(viii) वर्ष 1994-95 के दौरान डीoर्मoर्सo में अनुसूचित जातियो/अनुसूचित जनजातियों का नामांकन।	3,5
(ix) 1994-95 के दौरान आर०आई०ई०:आर०सी०ई० में सेवा पूर्व पाठयक्रमों में अनुसुचित जातियों/अनुसुचित	36

जनजातियों का नामांकन।

पस्तावना

1991 की जनगणना के अनुसार, देश में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या 13.82 करोड़ है और अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या 6.78 करोड़ है। दोनों की जनसंख्या मिलाकर यह मारत की जनसंख्या का 24.33 प्रतिशत है। ये सामाजिक तथा आर्थिक सीढ़ी का सबसे निचला वर्ग हैं। अनुसूचित जातियों के प्रति, स्वतन्त्रता प्राप्ति के पूर्व, समाज का रवेया उपेक्षा तथा मेद-माय का था और दूसरी नरफ अधिकांश अनुसूचित जनजातियाँ आदिम निवाह कर रही थी और वे शताब्दियों से मुख्य धारा से अलग थी। शिक्षा की दृष्टि से ये दोनों समूह हमारे देश के सर्वाधिक जिएड़े वर्ग हैं।

स्वतन्त्रता प्राप्त के पश्चात सरकार ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जतजातियों के शैक्षिक आधार का सुदृद करने के लिए कई पहलें की है। प्राथमिक आधार पर हुन समुदाय बहुल क्षेत्रों में शैक्षिक सस्थाओं की व्यवस्था करना, छायवृत्ति, निःशुल्कता, मध्याहन भीजन, वर्दियों, पुस्तकें और स्टेशनरीं, शैक्षिक संस्थाओं में स्थानों का आरक्षण, उच्च अध्ययन वाले सस्थानों में राखिलें संबंधी मानदण्डों में छूट, कंचिंग की व्यवस्था, छात्रावास की व्यवस्था, आदि जैसी पहलों की व्यवस्था जैसे ऐसे कदम उद्याएं हैं जिनसे उनकों शैक्षिक उपलब्धि में बहुत अधिक योगदान मिला है।

केन्द्रीय सरकार से कल्याण मणलय का संबंध ऐसी योजनाओं से है जो कंबल अनुसूचित जातियों और अनुसचित जनजातियों के लिए हैं। उत्तर मेट्रिक खाववांचयां, महिला और एरप छात्रावास, आश्रम स्कूल, मैट्रिक पूर्व छाप्रवृत्तियां जैसी कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं उन बच्चों के लिए हैं जिनके मारा-पिता सफाई संबंधी व्यवसाय में लगे। हुए हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं आदि के लिए उनके बास्ते कीचिंग कक्षाएं हैं।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय का शिक्षा विभाग अपने सभी कार्यक्रमां में अनुसचित जातियों और अनुसचित जनजातियों के शैक्षिक विकास पर विशेष बल देता है। शिक्षा विभाग द्वारा प्रदान की गई कुछ महत्वपूर्ण सविधाओं में से कछ निम्नलिखित हैं :-सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आई०आई०टी०) और क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेजों (आर०ई०सी०) में अनुसचित जातियों के लिए 15 प्रतिशत स्थान और अनुसूचित जनजातियों के लिए 7.5 प्रतिशत स्थान आरक्षित हैं। शिक्षा विभाग ने राज्य सरकारों/विश्वविद्यालयों को सलाह दी है कि वे सभी शैक्षिक संस्थानों में अनुसचित जातियों/अनुसचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित करें। उनसे अनरोध किया गया है कि वे विभिन्न पाठयक्रम में दाखिले के चयन संबंधी मानदण्डों में उस सीमा तक छट दें कि सारे आरक्षित स्थान अनुसचित जातियों/अनुसचित जनजातियों द्वारा भरे जा सके। छात्रवृत्तियां, अनुसंघान शिक्षावृत्तियां, शैक्षिक संस्थाओं के स्थानों का आरक्षण और जनजातीय भाषाओं में पाठयचर्या तथा पाठयपुस्तकें तैयार करना आदि की व्यवस्था करना अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक विकास के लिए विभाग द्वारा उठाए गए कार्यकलायों में से कुछ हैं। इसके अलावा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्रों में गैर-औपचारिक शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र खोलने में पार्थिमकता पदान की जाती है।

स्वास्थ्य और श्रम जैसे अन्य केन्द्रीय मंत्रालय अपने-अपने विशिष्ट होत्रों में शिक्षा से संबंधित कार्य करते हैं जहां वे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों को दाखिले, आदि के मामले में इस प्रकार की सुविधाएं मुहैया कराते हैं।

1. जनसंख्या पार्श्वचित्र

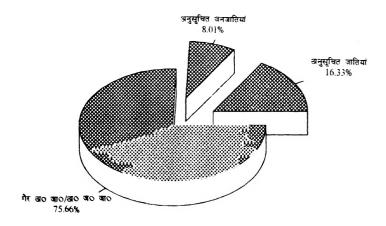
अनुसूचित जातियां

1991 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जातियों की जनसंख्या 13.82 करोड़ है जो देश की 84.63 करोड़ कुल जनसंख्या का 16.33 प्रतिशत है। पुरुष जनसंख्या 7.19 करोड़ और महिला जनसंख्या 6.63 करोड़ है जो देश की कुल जनसंख्या का क्रमशः 16.38 प्रतिशत और 16.29 प्रतिशत है। 1981 में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या कुल जनसंख्या का 15.8 प्रतिशत थी। नागालैंड और संघ राज्य क्षेत्र अण्डमान और निकोबार दीपसमूह और लक्षदीप में कोई अनुसूचित जातियों नहीं हैं।

अनुषुचित जनजातियां

1991 की जनगणना के अनुसार अनुसृचित जनजातियों की जनसंख्या 6.77 करोड़ है जो देश की कुल जनसंख्या का 8.01 प्रतिशत है। अनुसूचित जनजातियों की कुल जनसंख्या में 3.4 करोड़ पुरुष और 3.3 करोड़ महिलाएं हैं जो देश की कुल जनसंख्या का अन्नशः 7.8 प्रतिशत और 8.2 प्रतिशत हैं। 1981 में, अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या कुल जनसंख्या का 7.8 प्रतिशत और 18.2 प्रतिशत हैं। 1981 में, अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या कुल जनसंख्या का 7.8 प्रतिशत थी। हरियाणा, पंजाब, चंडींगढ़, दिल्ली और पांडिचेरी के राज्य/संघ राज्य हैं। में कोई अनुसूचित जनजातियां नहीं हैं। वर्ष 1991 के जम्मू और कश्मीर के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का एक विस्तुत पाश्वीचन्न संलग्नक-। में दिया गया है।

1991 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति एवम जनजाति की जनसंख्या



[चित्र 1]

2. साझरता सस्थित

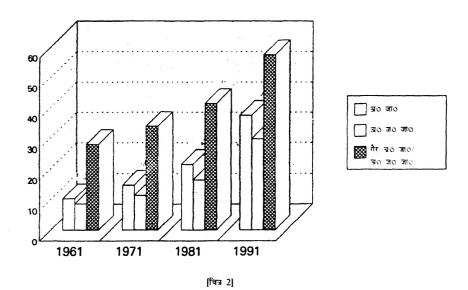
अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में शिक्षा की शुरुआत बहुत भीमी रही थी। इसका कारण स्वतन्त्रता प्राप्ति से पूर्व उनकी सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति थी। हालांकि स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात योजनाश्चद विकास के परिणामस्वरूप उल्लेखनीय प्रगति हुई है, फिर भी साक्षरता के मामले में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य जनसंख्या के बीच अब मी असमानताएं हैं। अनुसूचित जातियों में कुल साक्षरता वर्ष 1961 में 10.27 से बदकर वर्ष 1991 में 37.41 प्रतिशत हो गई है और अनुसूचित जनजातियों में यह 1961 में 8.54 प्रतिशत से बदकर 29.60 प्रतिशत हो गई है जो कि अन्यों के मुकाबले में बहुत कम है। तालिका-1 में पिछले तीन दशकों की साक्षरता दरों की एक तुलनात्मक तस्वीर प्रस्तुत की गई है।

तालिका-1 साक्षरता दर

वर्ष	अनु. जाति	अनु . जनजाति	गैर अनु. जाति/ अनु. जनजाति
1961	10.27	8.54	27.86
197 1	14.67	11.30	33.80
1981	21.38	16.35	41.30
1991	37.41	29.60	57.40

अनुस्चित जातियों और अनुस्चित जनजातियों के मामले में महिला साक्षरता अब भी असंतोषजनक हैं। 1991 में गैर अनुः जाति/जनजाति महिलाओं के लिए यह 44.96 प्रतिशत के मुकाबले, अनुसुचित जातियों के लिए यह केवल 23.76 प्रतिशत है और अनुसुचित जनजातियों के लिए यह 18.19 प्रतिशत है। 1991 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की राज्यवार साक्षरता दरें संलगनक-11 में दी गई हैं।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की साक्षरता दरें 1961-1991

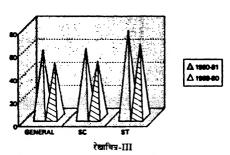


तालिका-2

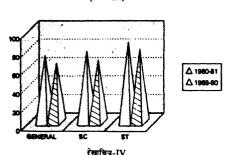
	अनुस्चित जा	तयां	अनुसूचित जनज	तियां	सामान्य	
कक्षाएं	1980-81	1989-90	1980-81	1989-90	1980-81	1989-90
I—V	60.16	49.03	75.66	63.81	58.70	48.08
I—VIII	76.84	67.62	86.71	79.35	72.70	64.09
I—X	86.91	79.42	91.18	86.28	82.46	74.46

वपर्युक्त तालिका में 1980-81 से 1989-90 तक की अविध के वैरान प्राथमिक, मिडिल और हाई स्कूल के स्तरों पर उनु० जातियों और अनु० जनजातियों के बच्चों द्वारा पढ़ाई जारी रखने के सम्बन्ध में हुए सुधार को वर्माया गया है। उनुसृष्वित जातियों के छात्रों द्वारा पढ़ाई बीच में छोड़ने की दर करीबन सामान्य जनसंख्या के बराबर है परन्तु अनु० जनजातियों के छात्रों द्वारा पढ़ाई बीच में छोड़ने वालों की दर वामी भी काफी उधिक है। वास्तव में कुल करें संवोधकानक नहीं है और कका-। से V तक तथा कका-। से VIII में क्रमशः 20 प्रतिकृत तथा 40 प्रतिकृत के ताठकीं पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उनको काफी नीचे सबने की जावश्यकता है। अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियों में राज्यवार पढ़ाई बीच में बोहने वाले छात्रों की दरें संलग्नक IV तथा V में दी गई हैं।

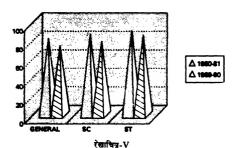
प्राथमिक स्तर पर पदाई बीच में खोड़ जाने वालों की दरें (I—V)



मिडिल स्तर पर पढ़ाई बीच में छोड़ वाने वालों की वरें (I--VIII)



माष्यमिक स्तर पर पदाई बीच में छोड़ जाने वालों की दरें (I—X)



II. नीति-निर्घारण

 राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में जिसे 1992 में अबतन किया गया या, उन लोगों की विशेष आवश्यकताओं पर ध्यान देते हुए श्रीक्षक अवसरों को एक समान बनाने और असमानताओं को दूर करने पर बल दिया गया है जिन्हें अब तक समानता से वंचित रह्या गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में श्रीक्षिक रूप से वंचित वर्गों, विशेषरूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों पर लक्षित किए जाने वाले विशेष प्रयासों के लिए नीति-निदेश प्रदान किए गए हैं।

अनुसूचित जातियों की शिक्षा पर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में यह कहा गया है:

अनुस्चित जातियों के शैक्षिक विकास पर केन्द्र द्वारा विशेष बल दिया जाएगा जिससे कि वे गैर-अनुसूचित जाति के लोगों के बराबर का सकें। यह बराबरी सभी क्षेत्रों और सभी स्तरों पर इन चारों आयामों में होनी जरूरी है, प्रामीण पुरुषों में, प्रामीण महिलाओं में, शहरी क्षेत्रों के पुरुषों में और शहरी क्षेत्रों की महिलाओं में।

इस प्रयोजन के लिए जिन उपायों पर विचार किया गया है उनमें से कुछ निम्न प्रकार है —

- (i) निर्धन परिवारों को इस प्रकार का प्रोत्साहन दिया जाए कि वे अपने बच्चों को 14 साल की उम्र तक नियमित रूप से स्कूल भेज सकें;
- (ii) सफाई कार्य, पशुओं की चमड़ी उतारने तथा चर्म-शोधन जैसे ध्यवसायों में लगे परिवारों के बच्चों के लिए मैटिक-पूर्व खात्रवृत्ति योजना पहली कक्षा से शुरू की जाएगी। ऐसे परिवारों की आय पर ध्यान दिए बिना, उनके परिवारों के सभी बच्चों को इस योजना में शामिल किया जाएगा तथा उनके लिए समयबद कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे:
- (iii) ऐसी सुनियोजित व्यवस्थाएं करना और उनकी पड़ताल की विधि स्थापित करना जिससे कि यह पता चलता रहें कि अनुसूचित जातियों के बच्चों के नामांकन होने, नियमित रूप से अध्ययन जारी रखने और पढ़ाई पूरी करने की प्रक्रिया में कई। गिरावट तो नहीं आ रही है। साथ ही इन बच्चों की आगे की शिक्षा और रोजगार पाने की सम्मावना को बढ़ाने के उद्देश्य से उनके लिए उपचारात्मक पाठयचर्या की व्यवस्था करना;
- (iv) अनुसूचित जातियों से शिक्षकों की मर्ती;
- (v) जिला केन्द्रों पर अनुसूचित जातियों के छात्रों के लिए छात्रावास
 की सुविधाएं क्रमिक रूप से बढ़ाने का प्रावधान;
- (vi) स्कूल-मवनों, बाल-वाड़ियों और प्रौद शिक्षा केन्द्रों का स्थान चुनते समय अनुसुबित जातियों के व्यक्तियों की पूर्ण रूप से सहमागिता को सुकर बनाना;

- (vii) जवाहर रोजगार योजना के संसाधनों का उपयोग करना जिससे कि अनुसूचित जातियों को पर्याप्त शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध क्षे सकें: और
- (viii) शैक्षिक प्रक्रिया में अनुसूचित जातियों की सहमागिता को बढ़ाने के लिए नए तरीकों की खोज को जारी रखना।

अनुसूचित जन-जातियों की शिक्षा पर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में यह उल्लेख किया गया है:

अनुसूचित जनजातियों को अन्य लोगों के बराबर लाने के लिए निम्नलिखित उपाय तत्काल किए जाएंगे:

- (i) अदिवासी इलाकों में प्राथमिक स्कूलों को खालने के कार्य को प्राथमिकता दी जाएगी। इन क्षेत्रों में स्कूल मवनों के निर्माण का कार्य शिक्षा के लिए सामान्य-निधियों जवाहर रोजगार-योजना, जनजातीय कल्याण योजनाओं, आदि के अन्तर्गत प्राथमिकता के अध्यर पर हाथ में लिया जाएगा:
- (ii) आदिवासियों की अपनी ही सांस्कृतिक विक्रिष्टता होती है और बहुषा उनकी अपनी बोलकाल की माषाएं होती है। पाठ्यक्रम निर्माण में तथा क्रिक्षण सामग्री तैयार करने में यह जरूरी है कि शुरूआत की अवस्था में आदिवासी माषाओं का प्रयोग किया जाए तथा इसका प्रबन्ध किया जाए कि आदिवासी बच्चे शुरू के कृछ वर्षों के बाद क्षेत्रीय माषा के माध्यम से शिक्षा प्राप्त कर सकें;
- (iii) शिक्षित तथा उधैयमान आदिवासी युवकों को प्रोत्साहित किया जाएगा और प्रश्निक्षित किया जाएगा जिससे कि वे आदिवासी क्षेत्रों में अध्यापन कर सकें;
- (iv) आग्रम स्कूलों सहित आवासीय-स्कूल बड़ी संख्या में स्थापित किए जाएंगे;
- (v) अनुसूचित जनजातियों के लिए उनकी विशेष आवश्यकताओं तथा जीवन-शैली को ध्यान में रखते हुए, प्रेरक योजनाएं तैयार की जाएंगी। उच्चतर शिक्षा के लिए खात्रवृत्तियां तकनीकी, व्यावसायिक और अर्थ व्यावसायिक पाठ्यक्रमों पर बल देंगी। मानसिक-सामाजिक अवरोधों को दूर करने के लिए तथा विमिन्न पाठयक्रमों में उनके निष्पादन में सुधार लाने के लिए विशेष उपचारी पाठयक्रम तथा अन्य कार्यक्रम प्रदान किए जाएंगे;
- (vi) अनुसूचित जनजातियों की बहुलता वाले क्षेत्रों में आंगनवाहियां.
 गैर-औपचारिक और प्रौद्ध शिक्षा केन्द्र प्राथमिकता के आधार पर खोले जाएंगे; और

(vii) क्रिक्क के सभी चरणों पर पाठ्यचर्मा आदिमजाति लोगों की समृद्ध त सांस्कृतिक-अस्मिता और उनकी विशाल सुजनात्मक प्रतिमा के स्वरं में भी उनमें चेतना के सुजन के लिए तैयार किर् जाएंगे।

कार्रवाई-योजना (का०यो०), 1992

- 1992 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 के संशोधन के अनुरूप, नीति-उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विस्तृत-कार्य-नीतियां निर्धारित करने हेतु एक नई कार्रवाई योजना 1992 में तैयार की गई थी। कार्रवाई-योजना में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के शैक्षिक विकास के लिए एक पूरा अध्याय (अध्याय-2) है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक विकास के लिए निम्नलिखित प्रमुखं उपाय- है:—
- अनुसूचित जातियों की बस्तियों और छोटे गांवों की आवश्यकताओं की
 पूर्ति के लिए प्राथमिक तथा अपर प्राथमिक स्कूलों को खोलने को प्राथमिकता
 प्रदान करना।
- ताठवीं पंचवर्षीय योजना से पूर्व प्रत्येक अनुसुचित जनजाति बस्ती में एक प्राथमिक स्कूल की व्यवस्था।
- जनजातीय क्षेत्रज्ञें में समेकित रूप में एक श्रीक्षक-योजना का क्रियान्वयन। स्कूल—पूर्व शिक्षा, ग्रैर-ज्ञीपचारिक शिक्षा, प्रारम्भिक शिक्षा और ग्रीद शिक्षा को जोड़नातांकि पूरी जनसंख्या द्वारा पूर्ण साक्षरता को प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जा सके।
- उन स्थानों पर जहां अनुसूचित जातियों के बच्चे औपचारिक स्कृलों में शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकते हैं, वहां ग़ैर-खीपचारिक और दुरस्थ-शिक्षा केन्द्रों की व्यवस्था करना।
- तन्०आ०/तान्०आ०आ० के निर्धन परिवारों के बच्चों को विशेष रूप से लहिकियों को स्कूलों में. खात्रवृत्तियों, वर्दियों, पाठ्यपुस्तकों, लेखन-सामग्री और मच्यान्ह-मोजन के रूप में पर्याप्त प्रोत्साहनों की व्यवस्था करना।
- दो वर्षों की अविध में आपरेशन-ब्लैक-बोर्ड योजना के अन्तर्गत समी जनजातीय क्षेत्रों और हरिजन बस्तियों को शामिल करना।
- -- प्राथमिक स्कूलों में प्रारम्भिक अवस्थाओं में जनजातीय समुदायों के बच्चों को उनकी मातुभाषा के माध्यम से पदाने की व्यवस्था करना।
- विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां मानक माषा और बोली मिन्न-मिन्न है, मानक अध्यापन/प्रशिक्षण सामग्री को उपलब्ध करना।

- प्रारम्भिक स्कूलों के लिए पहले ही निर्धारित न्यूनतम साक्षरता स्तर को प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करना।
- समी जनजातीय क्षेत्रों में प्रौद शिक्षा कार्यक्रम को शैक्षिक सूक्ष्म-आयोजना का एक अभिन्न अंग बनाना।
- पूर्ण साक्षरता प्राप्त करने के लिए पूर्ण साक्षरता अभियान के अन्तर्गत अनुञ्जाञ/अनुञ्जञ्जाञ की जनसंख्या पर ध्यान केन्द्रित करना।
- अनु**्जा**ं /अनु्ञ्जाञ्जाः क्षेत्रों में उत्तर साक्षरता केन्द्रों की स्थापना करना।
- श्रीक्षक उपलब्धि को बढ़ाने के उद्देश्य से कोचिंग, प्रशिक्षण और उपचारी अध्यापन कक्षाओं का आयोजन।
- माध्यमिक और सीनियर माध्यमिक कक्षाओं में अनुज्जाल/ अनुज्जज्जाल की छात्राओं के लिए अतिरिक्त छात्रवृत्तियों की व्यवस्था करना।
- मभी शैक्षिक संस्थाओं में दाखिले में आरक्षण का प्रमावी कियान्वयन और शिक्षकों की मर्ती।
- नवोदय विद्यालयों में या तो राष्ट्रीय मानदण्ड के आधार पर या जिले में अनुञ्जाञ/अनुञ्जञ्जाञ अनुपात की प्रतिशतता के आधार पर, जो मी अधिक हो, दाखिले में आरक्षण।
- संहार: अनुदान प्राप्त करने वाली प्राह्ववेट/सहायता प्राप्त संस्थाओं में आरक्षण का प्रावधान।
- शिक्षक बनने के लिए अनुजाज/अनुजजजाठ के छात्रों को प्रोत्साहित करना। शिक्षकों की योग्यता को सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए क्रैश-कार्यक्रम आरम्भ किए जाएंगे।
- अच्छी कोटि की शिक्षा प्रदान करने के लिए अनु०जा०/अनु०ज०जा० की बहुलता वाले क्षेत्रों में प्राथमिक से उच्चतर माध्यमिक तक गति-निर्घारक संस्थाओं की श्रृंखला स्थापित करना।
- अनुरुजार्य/अनुरुजरुजारु के छात्रों के छात्रावासों के स्तरों में सुधार करना।
- स्कूर्जी पाठयचर्या में डा० अम्बेडकर के दर्शन को शामिल करना।

क. शिक्षा विभाग

राष्ट्रीय शिक्षा नीति. 1986 के अनुसरण में शिक्षा विभाग ने विद्यमान अर्थक्रमों को जारी रखने के अलावा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक विकास के लिए कई उपाय आरम्भ किए हैं। इस अर्थक्रम में शिवा के सभी स्तर शामिल हैं।

1. प्रारम्भिक शिक्षा

प्रारम्भिक शिक्षा को सभी को सलभ कराना संविधान के अनुन्छेद 45 में राज्य के 14 वर्ष की आयु तक सभी बच्चों को नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के दायित्व का उल्लेख किया गया है। संवैधानिक निर्देशों के अनुसरण में प्रारम्भिक शिक्षा सभी को सुलभ कराने के लिए शिक्षा विभाग ारा कई उपाय किए गए हैं। इन कार्यक्रमों में अनुसूचित जातियों और अनुसचित जनजातियों के लिए विशेष उपाय शामिल किए जाते हैं। प्रारम्भिक शिक्षा को सभी को सुलम कराने में उस तक पहुंच का होना ही प्रमुख महा है। अनुस्रवित जातियों और अनुस्रवित जनजातियों के बच्चों की प्राथमिक शिक्षा हेतु पहुंच को बढावा देने के उद्देश्य से प्राथमिक स्कूल खोलन सम्बन्धी मानदण्डों जिनमें सामान्यतया ,3(X) की जनसंख्या बस्ती से एक किलो मीटर पैदल दूरी होती है, इसे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित उनजातियों के मामले में इस मानदण्ड को 200 की जनसंख्या की बस्ती की एक किलो मीटर पैदल दुरी के अन्दर प्रार्थामक स्कल उपलब्ध कराकर इसे गर्नाला बनाया गया है। सभी राज्य सरकारों ने सरकारी स्कूलों में कम से कम अपर प्राथमिक स्तर पर शिक्षा शुल्क समाप्त कर दिया है। अधिकांश राज्यों में स्थानीय निकायों और निजी सहायता प्राप्त संस्थाओं द्वारा चलाए जाने वाले स्कूलों में भी शिक्षा नि:शुल्क है।

अधिकांश राज्यों द्वारा आर्थिक दृष्टि से पिज हों. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जानजातियों के अच्यों को शिक्षा के अच्या खर्चे जैसे गठयपुस्तकों, वर्दियों. स्कूल, अस्तों, पित्वहन आदि सम्बन्धी लागत की दृग करने के लिए सहायता दी जाती है। किन्तु उत्तकों संख्या बहुत कम है। यांच्ये अखिल भारतीय श्रीक्षिक सर्वेद्राण की वर्ष 1986 की रिपोर्ट के अनुसार गर्थामिक तथा अपर ग्राथमिक स्तरों पर 1.46.36.266 बच्चों को निःशुलक वर्दियां प्रदान की गई जो प्रारम्भिक स्तर पर वाचिल खाओं का मात्र 12 प्रदिशत है। स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर 1.60.73,242 खाओं को मुक्त वर्दियां मिली। उनमें से, 33.04 प्रतिशत खात्र अनुसूचित जातियों के तथा 11.50 प्रतिशत छात्र अनुसूचित जातियों के तथा 11.50 प्रतिशत छात्र अनुसूचित जात्रजारियों से हैं। साममोगियों में से 77.44 प्रतिशत प्रामीण क्षेत्रों के हैं।

आपरेशन ब्लैक बोर्ड : अप्येशन बौकबोर्ड को प्राथमिक स्कूलों में न्यूनतम अनिवार्य अवस्थापना प्रवान करने के लिए तैयार किया गया। इसे एस्ट्रीय शिक्षा नीति. 1986 के अनुसरण में वर्ष 1987 में शुरू किया गया। इसे एस्ट्रीय शिक्षा नीति. 1986 के अनुसरण में वर्ष 1987 में शुरू किया गया। इसके तीन उद्देश्य हैं (क) सभी प्राथमिक स्कूलों में कम से कम दो शिक्षकों का प्रावधान: (ख) प्रत्येक स्कूल में अनिवार्य शिक्षण/अध्ययन सामग्री को सुनिश्चित करना: तथा (ग) सभी मौसमों के लिए भवन में प्रत्येक स्कूल में कम से कम दो कमरों का प्रावधान। 31 अगस्त, 1995 को, 522, 902

प्राथमिक स्कूलों को शिक्षण अध्ययन सामधी संस्वीकृत की गयी। 150,000 शिक्षकों के पद संस्वीकृत किए गए हैं जिनमें से 125,000 पद मरे जा चुके हैं। लगभग आधे पद महिला उम्मीदवारों से भरे गए हैं, 150,000 स्कूल कमरों का निर्माण किया गया है। इस स्क्रीम पर अब तक 1,280 मिलियन स्पए की राशि खर्च की गयी है। आठवीं पंचवर्षीय योजना की श्रेष अवधि के तैरान आपरेशन ब्लैकओई की योजना के तहत श्रेष प्राथमिक स्कूलों को भी इसमें शामिल किए जाने का प्रस्ताव है। इसका अर्थ यह हुआ कि अनुसचित जातियों जनजातियों को बर्मत्यों में स्थित सार्पाण प्राथमिक स्कूलों को आपरेशन ब्लैकओई के तहत शामिल किया जाएगा। प्राथमिक स्कूलों को अपर प्राथमिक स्कर पर शामिल किए जाने के लिए 3 शिक्षकों और 3 कमरों का प्राथमिक कार पर शामिल कर के इस योजना को कम्यान्यत करते समय अनुस्चित जातियों और अनुसूचित जातियों के बाहुएय वाले क्षेत्रों के प्राथमिकता प्रदान करने के लिए राज्य सरकारों को विदेश दिए गए है।

अनौपचारिक शिक्षा : अनोपचारिक शिक्षा को शिक्षा पर भारत की वर्तमान कार्यनीति के महत्वपूर्ण पहलू के रूप में देखा जाता है क्योंकि इसकी पहुंच कामकाती अच्छों लड़िक्यों और उन अच्छों तक है जा कई सामाजायिक कारणों से पूर्णकालिक स्कूल में शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते। राज्य सरकारों तथा स्वैन्दिक संगठनों के अरिए कार्योंक्वन और -श्रीपचारिक शिक्षा कार्यक्रम सामुदायिक भारतारी के उच्च स्नर पर बल देना है और लचीलापन, आसंशिकता और एक विकेन्द्रीकृत प्रशासनिक संग्वना इसकी विशेषलाएं है। इस योजना से अनुसूचिन जातियों तथा अनुसूचित जनातिया सिहन सभी समुदायों के बच्चे लाभानियन हो रहे हैं। अब तक 2 60,000 अनौपचारिक शिक्षा केन स्थापित किए गए है जो 6.5 मिलायन बच्चों की लाभभा की प्राप्त कर रहे हैं। केवल लड़िक्यों के लिए ही लाभभा 100000 केन्द्र हैं। 450 से अप्रकारी सरकारों सरहत्व / एँ -श्रीपचारिक शिक्षा केन कार्यों के स्थान की स्वाप्त केने कारण की स्थान की स्वाप्त की स्थान की स्वाप्त की स्वा

जिला पार्थामक शिक्षा कार्यकरमः भारत में पार्थामक शिक्षा वदति को दुरुस्त बनाने के लिए प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का एक परिशिशीर्ष के कृष में परिकल्पित किया गया है। अनेक राज्य स्तरीय शुक्राअली की एनुख विशेषताओं को तैयार करने के साथ-साथ संचित राष्ट्रीय अनुभव की मजबूत बनाते हुए, यह कार्यक्रम मिशन रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम पूर्व-योजनाबद्ध खण्डश दृष्टिकोण से हटकर प्रारम्भिक शिक्षा के व्यापक दृष्टिकोण को अपनाता है तथा विकेन्द्रीकृत प्रबन्ध और समदाय गतिशीलता पर बल देता है और जिला तथा जनसंख्या विशिष्ट योजना को जारम्भ करता है। यह केन्द्र सरकार द्वारा प्रायंजित योजना है और विन पोपण का केन्द्रीय हिस्सा बहुपशी तथा द्विपशी स्रोतों से जुटाया जाता है। जिल्ह्याल्डिक कार्यक्रम और शिक्षा की विषयवस्तु, प्रक्रिया, गुणवता तथा एकरूपता की ओर ध्यानाकर्षित करने जैसे परम्परागत पैकेजों की सीमा को पार कर जाता है। इस कार्यक्रम में प्राथमिक शिक्षा के विकास में शैक्षिक मुद्दों का समेकित दुष्टिकोण निहित है और राज्य तथा स्थानीय स्तरों पर संस्थानिक क्षमता के निर्माण एवं सुदुर्दीकरण अपेक्षित है ताकि प्रा०शि० के सर्वसुलमीकरण की चुनौतियों को पूरा कर सके।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम को कार्रवाई योजना 1992 में परिकारियत जिला विशिष्ट कार्यनीति के अनुसरण में तैयार किया गया है। जिञ्जाञ्चार परियोजना के विशिष्ट उद्देश्य इस प्रकार हैं:—

- (i) लोगों तथा सामाजिक वर्गों में दाखिला, पदाई बीच में छोड़ जाने बालों और अध्ययन उपलब्धियों में व्याप्त अन्तराल को पांच प्रतिशत से कम करना।
- (ii) सभी छात्रों के लिए समग्र प्राथमिक स्कूल बीच में छोड़ जाने वालों की दर को दस प्रतिशत से भी कम तक लाना।
- (iii) समी प्राथमिक स्कृली बच्चों में औसत उपलब्धता स्तरों को अकि गए आधार रेखीय स्तरों से कम से कम 25 प्रतिशत तक बढ़ाना और आधारमृत साक्षरता तथा अकिय क्षमताओं तथा अन्य क्षमताओं में न्यूनतम 40 प्रतिशत उपलब्धता सुनिश्चित करना, तथा
- (iv) राष्ट्रीय मानदण्डों के अनुसार, प्राथमिक शिक्षा कक्षाओं (I से V) तक सभी बच्चों को इसे मुद्देया कराना अर्थाद जब भी सभव हो, प्राथमिक स्कूल शिक्षा अथवा इसके समकक्ष अनीपचारिक शिक्षा।

जिलों के चयन के मानदण्ड के ब्रमुसार उन जिलों का चयन किया जाएगा जहां वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर राष्ट्रीय बीसत से कम है तथा जहां कुल साक्षरता अभियानों ने सफलतापूर्वक शिक्षा के लिए मांग जुटायी है।

आठवी पश्चर्यीय योजना के तैरान एक चरणश्च तर्राक्र से 110 जिलों की इसमें शामिल करने का लक्ष्य है। जब तक मान राज्यों मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल, हरियाणा, कर्नाटक और अमम के 42 जिलों की इस कार्यक्रम के तहत शामिल किया गया है। ये हैं:— असम में धुबड़ी, दाराग, मीरिगांव नथा कारबों; हरियाणा में मिरमा, हिमार, जींद और कैयल, कर्नाटक में कोलार, मध्य बेलगाम तथा रायचुर, महाराष्ट्र में औरिगाबाद, उम्मानाबाद, नानदेड, परभानी और लाहुर, तमिलनाडु मं भीपी, रायपाद, मरपूजा, पन्ना, और दक्षिणी अरकोट तथा मध्य प्रदेश में भीषी, रायपाद, मरपूजा, पन्ना, टीकमगढ़, शाहडांल, घार, छत्तपपुर, सिहनोर, रायसंन, रायपाद, रीवा, बिलासपुर, सनना, राजनन्दगांव, मन्दभीर, रतलाम और बेनुल।

इन जिलों में से, मध्य प्रदेश में 9 जिले अर्थात सीधी, सरगुजा, बिलासपुर, घार, शाहडोल, रतलाम, रायगढ, राजनन्दगांव और बेंचुल बनजातीय उप योजना क्षेत्र सहित जनजातीय बाहुल्य वाले जिले हैं।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम में विशेष रूप से योजना और वजर के कार्यन्वयन के साथ-साथ अनुस्चित जनजातियों की प्राथमिक शिक्षा में युधार हेतु आदिवासी जिलों के लिए कार्यनीतियां तैयार करने तथा कम से कम संगत जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम वाले जिलों में जनजातीय जनसंख्या के भाग के अनुपात में आदिवासी छात्रों हेतु परियोजना संसाधन भाषित करने सम्बन्धी व्यवस्था की जाती है।

जनजातियों की वर्तमान स्थिति का निर्धारण करने और उनकी विशेष आवश्यकताओं का पता लगाने की दृष्टि से सात राज्यों के 15 जिलों में अध्ययन किए गए थे ताकि जनजाति विशिष्ट कार्यक्रम नैयार किए जा सकें। जनजातियों की शिक्षा के लिए विशिष्ट विशेषताएं निम्न प्रकार से हैं:

- जनजाति आश्रादी में नए स्कूल
- समुचित बाल विकास सेवाओं और शिशु सदनों जैसे अन्य केन्द्रीय और राज्य कार्यक्रमों के साथ मजबूत सम्पर्क जो सहोदर माई या बहनों की देखमाल करने में सहायता करेगी ताकि लड़की स्कूल में जा सके। जनजातीय भाषाओं में अनुपूरक शिक्षण सामग्री।
- -- शिक्षकों और शैक्षणिक प्रशासन की जनजातियों में विशेष रुचि लेना।
- जनजातीय शिक्षकों की नियुक्ति
- जनजातीय भाषाओं में शिक्षकों के प्रशिक्षण को महत्व देना
- आश्रम स्कूल
- दिभाषी प्रवेशिकाएं (जनजातीय भाषा और हिन्दी)
- जनजातीय क्षेत्रों से विशेषतः सम्बन्ध रखने वाली णठयपुस्तकें

— मध्य प्रदेश में प्रशासनिक ढांचे को युक्तिसंगत बनाना। अब तक स्कृतों का प्रबन्ध जनजाति कल्याण और स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा किया जाता था। जनजाति जिलों में अब इन सब स्कूलों का प्रबंध जनजाति कल्याण विभाग द्वारा किया जाएगा। अन्य जिलों में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा किया जाएगा। गञ्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् शैक्षिक और प्रशिक्षण सहायता देगी।

कार्यग्रम का एक मुख्य प्राचल यह है कि राज्य जनजातीय छात्रों के लिए परियोजना संसाधनों को कम से कम जिले की आबादी में जनजातियों की आबादी के हिस्से के अनुपात में आबंदित करेंगे। उदाहरणार्थ मध्य प्रदेश में जिला स्तर के कार्यों के लिए कुल प्रस्तावित 454.79 करोड़ ए० में से मध्य प्रदेश के जनजातीय जिलों के लिए 197.63 करोड़ ए० आबंदित किए गए। यह निष्यों का 40 प्रतिशत है जो जनजातीय आबादी के अनुपात से अधिक है।

लोक जुम्बिश : लोक जुम्बिश का लक्ष्य राजस्थान में 2000 ईसवी तक सभी के लिए शिक्षा प्राप्त कराना है। इस कार्यक्रम का लक्ष्य मुल्स्मृत शिक्षा पदित में पहुंच और सहभागिता को बदाना है तथा यह विशेष रूप से समाज के वैचित वर्गों के बच्चों पर केन्द्रित है। इस परियोजना में ग्राम स्तर पर सुक्ष आयोजना के जरिए अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के बच्चों के लाभ के लिए विशेष कार्यनीतियां तैयार की जाती हैं। इस परियोजना के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के परिवारों के बच्चों के लिए निःशुल्क वर्दियों तथा पाठ्यपुस्तकें वितरित की जा रही हैं और कम लागत के छात्रावासों तथा आश्रम शालाओं का निर्माण भी किया जा रहा है। लोक जुम्बिश परियोजना का कार्यक्षेत्र निम्नलिखित अनुसूचित जातियों/अनुसचित जनजातियों के संकेन्द्रण वाले खण्डों में हैं:—

अनुसूचित जाति बहुल स्वण्ड स्वण्ड किशनगंज गदी चोहर्रो शाहबाद झालरापाटन बिश्वीवारा प्रतापगद

झाहोल

धानगाजी

II. माध्यमिक शिक्षा

नि:शृत्का शिक्षाः आन्ध्र प्रदेशः असमः बिद्वारं (सरकारी स्कूलों में) हिमाचल प्रदेश (सरकारी स्कूलों में) कर्नाटकः तमिलनाडु (सरकारी स्कूलों में) और लक्षदीप में माध्यमिक स्तर तक (कक्षा X तक) शिक्षा निःशृत्क है। अरुणाचल प्रदेशः गोवाः जम्मू और कश्मीरः केरलः सिक्किम (सरकारी स्कूलों में) त्रिपुरा, पश्चिम बंगालः अण्डम्मन और निकोबार दादर और नगर

हवेली. दमन और दीव, पांडिबोरी तथा मध्य प्रदेश में सीनियर माध्यमिक स्तर (कक्षा XII) तक नि:शुल्क शिक्षा प्रवान की जाती है। गुजरात में लड़कों को कक्षा XI तक और लड़कियों को कक्षा XII तक नि:शुल्क शिक्षा प्रवान की जाती है। हरियाणा (सरकारी स्कूलों में), पंजाब (सरकारी स्कूलों में), मणिपुर. राजस्थान (सरकारी स्कूलों में), उत्तर प्रदेश. दिल्ली और बण्डीगढ़ में लड़के और लड़कियों को कक्षा आठ तक शिक्षा नि:शुल्क दी जाती है। हरियाणा (सरकारी स्कूलों में), महाराष्ट्र. राजस्थान (सरकारी स्कूलों में), कार प्रदेश और वारत प्रदेश और वारत प्रदेश और अपना के सिंग हिंग स्कूलों में लड़के यो को कक्षा XII तक शिक्षा नि:शुल्क दी जाती है। महाराष्ट्र में सरकारी स्कूलों में लड़के के कक्षा VII तक शिक्षा नि:शुल्क दी जाती है। महाराष्ट्र में सरकारी स्कूलों में लड़के और लड़िकयों को क्रमा प्राया कि शक्षा नि:शुल्क दी जाती है। महाराष्ट्र में सरकारी स्कूलों में लड़के और लड़िकयों को क्रमा प्राया नि:शुल्क दी जाती है। महाराष्ट्र में सरकारी स्कूलों में लड़के और लड़िकयों को क्रमा प्राया नि:शुल्क प्रयान की जाती है। महाराष्ट्र में सरकारी हो शक्षा नि:शुल्क प्रयान की जाती है।

नवोदय विद्यालयः प्रतिभावान बच्चों मुख्यतया प्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को अच्छी कोटि की आधुनिक शिक्षा प्रवान करने के उद्देश्य से मारत सरकार ने एक जिले में औसतन एक नवोदय विद्यालय स्थापित करने के लिए वर्ष 1985-86 में एक योजना आरम्भ की। अब तक 24 राज्यों और 6 स्व राज्य क्षेत्रों में तीन सी प्रचास नवोदय विद्यालय स्थापित किए जा चुके हैं। 31 मार्च 1994 की स्थित अनुसार स्कूलों में कक्षावार दाखिला तालिक। 3 में दिया गया हैं!

तालिका-3
31-3-94 की यथास्थिति अनुसार नवोदय विद्यालयों में
दाखिला

कक्षा	गैर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	कुल
VI	13449	4855	3083	21187
VII	12426	4218	2408	19052
VIII	10992	3316	1822	16130
IX	9352	2868	1387	13607
x	9304	3044	1515	13868
XI	5550	1667	836	8053
XII	5148	1400	762	7310
योग	66121	21368	11813	99302

दाखिले की संख्या से पता चलता है कि 31 मार्च, 1994 की यथास्थित अनुसार कुल वाखिलों में 21.52 प्रतिशत खात्र अनुसूचित जाति के और 11.90 प्रतिशत खात्र अनुसूचित जनजाति के थे। इन स्कूलों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जातियों के राज्यवार वाखिले संलग्नक vi में दिए गए है।

नवादय विद्यालयों में, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बच्चों के पक्ष में सीटों का आरक्षण संबंधित जिले में उनकी आबादी के अनुपात में प्रदान किया जाता है बशरों कि किसी मी जिले में इस प्रकार का आरक्षण राष्ट्रीय औसत से कम हो। स्टाफ की नियुक्ति के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए सीटों के आरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धान्तों का नवोदय विद्यालय समिति, उसके क्षेत्रीय कार्यालयों और विद्यालयों द्वारा पालन किया जा रहा है।

केन्द्रीय विद्यालय : केन्द्रीय विद्यालय संगठन की स्थापना वर्ष 1965 में मुख्यतया रक्षा कार्मिकों सिंहत केन्द्रीय सरकार के स्थानान्तरणीय कर्मवारियों के उन बच्चों की शैक्षणिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की गई थी जिनकी शिक्षा में उनके अभिभावकों की एक माषायी क्षेत्र से दूसरे माषायी क्षेत्र में बारंबार स्थानान्तरण से और पाठयक्रम में परिणामिक परिवर्तन से बाधा पहती है। संगठन भारत सरकार द्वारा पूर्णतः वित्त पोंपित है। 31 मार्च, 1995 की स्थित अनुसार 818 केन्द्रीय विद्यालय हैं।

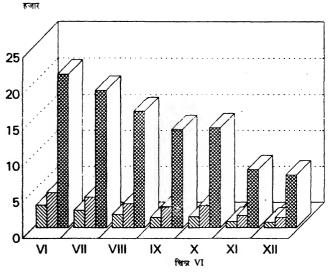
केन्द्रीय विद्यालयों ने नए दाखिलों का 15 प्रतिशत और 7.5 प्रतिशत क्रमशः अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित किया। यदि आवश्यक होता है तो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदयारों को अर्डक मानदण्डों में छूट दी जाती है।

30 अप्रैल, 1994 की स्थिति के अनुसार 796 केन्द्रीय विद्यालयों में अनुसूचित जातियों के 70,096 और अनुसूचित जनजातियों के 16,622 छात्र थे जो कुल नामांकन का फ्रमशः 10,30 प्रतिशत और 2,44 प्रतिशत है।

केन्द्रीय विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती में अनुसूचित जातियों के लिए 15 प्रतिशत और अनुसूचित जनजातियों के लिए 7.5 प्रतिशत आरक्षण का पालन किया जाता है। भर्ती के समय अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को निम्नलिखित रियायतें और छूटें दी जाती हैं:—

- (क) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों से आवेदन शुल्क नहीं लिया जाता।
- (ख) जहां पर्याप्त संख्या में उम्मीदवार नहीं होते वहां न्यूनतम (कट ऑफ) अंकों का ध्यान किए बिना अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों के सभी पात्र उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है।

कक्षा VI से XII तक 31.3.94 की स्थिति के अनुसार नवोद्य विद्यालयों में दाखिला





- (ग) आयु में पांच वर्ष की छूट दी जाती है।
- (घ) छूट मानकों के अन्तर्गत अलग से साक्षात्कार आयोजित किये जाते हैं।
- (ङ) साक्षात्कार बोर्ड द्वारा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों की पांच रियायती क्षेक दिए जाते हैं।
- (च) यदि आवश्यक होता है तो अनु ० जातियों/अनु ० जनजातियों हेतु आरक्षित पदों के लिए विजापन अलग से दिये जाते हैं।
- (छ) चयन समिति/विभागीय पदोन्नित समिति में अनु० जातियों/अनु० जनजातियों से सम्बन्धित एक सदस्य शामिल किया जाता है।

III. विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कनिष्ठ अनुसंघान अध्येतावृत्ति परीक्षा के लिए अनु० जातियों/अनु० जनजातियों के उम्मीदवारों को न्यूनतम अंकों में 10 प्रतिशत की रियायत दी जाती है तथा कनिष्ठ अनुसंघान अध्येतावृत्ति में आहंता प्राप्त करने वाले अनु० जातियों, अनु० जनजातियों के सम्भे उम्मीदवारों को अध्येतावृत्ति प्रदान की जाती है। यदि कोई खाली स्थान उपलब्ध नहीं है तो रिअठआ० विश्वविद्यालयों के लिए कनिष्ठ अनुसंघान अध्येतावृत्ति के अतिरिक्त स्थानों की व्यवस्था करता है। अनुसूचित जातियों/अनुसुचित जनजातियों के उन उम्मीदवारों को प्रति वर्ष पन्नस कानिक्की उनुसंखान अध्येतावृत्तियाँ सामाजिक विज्ञान सहित विज्ञान और मानिक्की विषयों में प्रदान की जाती है जो लेक्चरारिंगि हेतु राष्ट्रीय पात्रज्ञ परीक्षा में माग लेते हैं तथा लेक्चरारिंगि के लिए पात्रता संबंधी परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं।

संबद कालेजों में कार्यरत अनु० जातियों/अनु० जनजातियों से संबंधित अध्यापकों को अवसर प्रदान करने की दृष्टि से, अनु० जातियों/अनु० जनजातियों की प्रेणियों से संबंधित अध्यापकों को प्रत्यक्ष पुरस्कार की वि० अनु० आयोग की योजना के अन्तर्गत 50 अध्यापक अध्येतावृत्तियां (20 पी०एच०डीं० के लिए और 30 एम०फिल० के लिए) संस्थापित की गई है। 1993-94 के दौरान वि० अनु० आयोग ने 50 अध्यापक अध्येतावृत्तियां (20 पी०एच०डीं० और 30 एम०फिल०) प्रदान की हैं।

अनु० जातियों/अनु० जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए प्रति वर्ष अनुसंधान सहवृत्तियों के 40 स्थान निर्धारित किए जाते हैं। 1993-94 के तैरान, वि० अनु० आयोग ने वर्ष 1992 के लिए 40 पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं की सुषी को अन्तिम रूप दिया है और 1993 से सम्बन्धित पुरस्कारों के लिए अवेदन अमंत्रित किए हैं।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनकातियों के दाखिले वाले और पिछड़े क्षेत्रों में स्थित कालेजों से वित्तीय सहायका देने के बारे में मानदण्डों को शिष्यिल भी करता है।

बोयोग ने विश्वविद्यालयों और कालेजों में अनु० जाति/अनु० जनजाति के सात्रों के लिए उपचारी पाठ्यक्रम आरम्म करने की एक योजना तैयार की हे। वे कालेज/विश्वविष्यलय, जिनमें 15 प्रतिशत से अधिक अनु० जातियों/अनु० जनजातियों के छात्र वाखिल हैं, वहीं सहायता के आवेदन करने के **पात्र हैं**।

अवर स्नातक/उत्तर स्नातक स्तर पर उपचारात्मक शिक्षण का आयोजन इन बातों को ध्यान में रखकर किया जाना है (क) विभिन्न विषयों में हाजों की शैक्षिक दक्षता तथा पाखात्मक प्रवीणता को सुधारता, तथा (ख) ऐसे विषयों में हाजों के ध्याख्यात्मक स्तर को बद्धाना जड़ा माजात्मक प्रविधियां तथा प्रयोगशाला कार्य निहित है जिससे कार्यक्रम के अन्तर्गत दिए पर वावश्यक मागांदर्शन तथा प्रशिक्षण से बाजों को कार्यक्षमका के साथ अध्ययन करने सम्बन्धी अध्ययमक स्तर तक लाया जा सके। विश्वविद्यालयों/कालेजों में शिक्षण कहातों में विभिन्न विषयों में प्रवेश के क्षिए प्रवेश पूर्व परीक्षा/टेस्ट को भी सम्मिलित किया जा सकता है।

विभिन्न विश्वविद्यालयां/संस्थाओं में विशेष संलों की स्थापना इस इंग्डिट से की गई है ताकि खन्न जातियों/अनु अनजातियों के खानों के लिए विभिन्न योजनाओं के कारगर कार्यान्त्रयन को सुनिश्चित किया जा सके।

वर्ष 1993-94 में, वि० अनु० आयोग ने दो विभवविष्णलयों के विभिन्न सेलों की स्थापना के प्रस्ताव स्वीकार किए थे। इस प्रकार इन सेलों की कुल संख्या बढ़कर 97 हो गई है।

विश्वविद्यालय अनुरान आयोग अनु ७ जाति/अनु ७ जनजाति सेलों को चलाने के लिए विमिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए विश्वविद्यालयों को सहायता प्रदान करता है। वि०अ०आ० की सहायता कर्मचारियों को पहली नियुक्ति की तारीख़ से पांच वर्ष की अविध के लिए दी जाती है। फिलहाल, आयोग ने 31 मार्च, 1997 तक सेलों को चलाने के लिए सहायता देने का निर्णय लिया है। तत्यश्चात आवर्ती दायित्वों की निमाने का तत्तदायित्व राज्य सरकारों का होगा।

IV. तकनीकी शिक्षा

सामदायिक पोलिटेक्निक योजना—सामुदायिक पोलिटेक्निको की योजना 1978-79 में 36 पोलिटेक्निकों में प्रत्यक्ष केन्द्रीय महायता योजना के बन्तर्गत एक प्रयोगात्मक आधार पर संस्थापित की गई थी ताकि तकतीकी शिक्षा प्रणाली में किए गए निवेशों के लामों का एक उचित हिस्सा ग्रामीण समाज के लिए सुनिश्चित किया जा सके। सामुदायिक पॉलिटेक्निको की योजना का उद्देश्य निम्नतर स्तर पर जनता की सहभागिता और लघु स्तरीय आयोजना के माध्यम से सामाजिक तथा आर्थिक उन्नति के लिए और ग्राम आदमी के जीवन की कोटि में सधार लाने के लिए विज्ञान और पौद्योगिकी का अनुप्रयोग करके और पर्यावरण को कोई क्षति पहेचाये बगैर निरंतर सामाजिक विकास करना है। यह योजना गरीबी उन्मुलन, रोजगार के अवसर बनाने तथा आयु, लिंग अथवा शैक्षिक योग्यता की किसी पूर्व शर्त के बिना तकनीकी/व्यवसायिक क्षेत्रों में प्रवीणता उन्मुख विशिष्ट गैर-औपचारिक आवश्यकता पर आधारित अल्पकालीन पशिक्षण हारा नारी उत्पीहन को समाप्त करने पर बल देती है। यह प्रशिक्षण विशेषतया बेरोजगार/ अल्पनियोजित युवा/विद्यालय/कालेज-की पदाई बीच में छोड़ने वाले सविधारहित और लामों से वंषित वर्गी, महिलाओं, अल्पसंख्यकों तथा समाव के कमजोर वर्गों की जरुरतों को पूरा करने के लिए है। सामदायिक पोलिटेक्निक समुदाय के लिए प्रौद्योगिकी अंतरण, तकनीकी सहायता तथा विज्ञान और प्रोद्योगिकी के प्रति जागरुकता उत्पन्न करने वाले कार्यों को भी काते है।

अपने संस्थागत दांचे तथा कार्यजाल द्वारा सामुदायिक पोलिटेक्निक में ग्राम पंचायतों, जिला परिषद, प्रत्यायित स्वैच्चिक संस्थाओं आदि के माध्यम से समाज में निम्नतम स्तर पर सम्बंध स्थापित करते हैं तथा दूर-दराज के गांवों में विस्तार केन्द्रों की स्थापना करते हैं। ग्रामीण प्रौधोगिकों के विकास केन्द्र सामुवायिक पोलिटेक्निकों के लिए अनुसंघान एवं विकास पर बल देने वाली प्याली के रूप में उनके विकास, नवींकरण, नई तकनीक अपनाने, अनुकूल बनाने, सरल तथा ग्रामीण आवश्यकताओं के अनुरूप सही तथा सुसंगत लागत प्रभावी ग्रौधोगिकों के समावेश के लिए कार्य कर हैं। क्षेत्रीय तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाएं शैक्षिक, तकनीकी तथा प्रबन्धात्मक कहायता तथा मार्गदर्शन के लिए सामुवायिक पोलिटेक्निकों/ग्रामीण प्रौधोगिकों के विकास केन्द्रों के वास्ते संसाधन संस्थान के रूप में कार्य करती है।

रोजगार के खबसर जुटाने के उद्देश्य से कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए सम्बन्धित क्षेत्र सामाजिक-आर्थिक स्थितियों के अनुकृत लगामग 100 तकनीकी/व्यवसायिक कार्यों की पहचान की गई है। विभिन्न पाठयक्रमों में प्रवेश के लिए कोई निम्नतम शैक्षिक योग्यता निर्धारित नहीं की गई है। तथापि, महिलाओं, अल्पसंख्यकों तथा पढ़ाई बीच में छोड़ने वालों को प्रोत्साहित किया जाता है। देश में सभी निर्धारित उल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों (संख्या में 41) को इस योजना के अन्तर्गत पहले ही सम्मिलित कर लिया गया है। सामुदायिक पोलिटेष्टिनक निम्नलिखित कार्य करते हैं:—

सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षणः जनशक्ति विकास तथा प्रशिक्षणः प्रौद्यांगिकी अंतरण उद्यमशीलताः विकास के प्रति तकनीकी तथा सहायता सेवाएं: और सुचना का प्रसार

सामुदायिक पोलिटेक्निकों की योजना में अनुसंघान एवं विकास सह्ययता के लिए ग्रामीण प्रौद्योगिकी के विकास केन्द्रों की स्थापना मी सम्मिलित है।

सामुदायिक पॉलिटेक्निकों के लिए उनुसंघान और विकास प्रणाली के तौर पर ग्रामीण आवश्यकताओं के लिए उपयुक्त और सम्बद्ध प्रौद्योगिकों के विकास, संशोधन और उपनाए जाने के लिए सीoडीoआरoटीo के तौर पर अभी तक 31 डिप्लोमा स्तर के संस्थानों का चयन किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत सीoडीoआरoआईo को अलग से अनुदान प्रदान किया जा रहा है।

सामुदायिक पॉलटेक्निकों ने हूर दराज के प्रामीण क्षेत्रों में विस्तार केन्द्रों को स्थापित किया है ताकि इस प्रणाली के माध्यम से उपलब्ध कराई जा सकने वाली सेवाओं और सुविधाओं को सीधे गांवों में उपलब्ध कराया जा सके। पॉलिटेक्निकों ने, प्रामीण क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी की परीक्षित और अनुमोदित मदों का बही संख्या में अंतरण करने में महत्वपूर्ण योगदान द्विया है। इसमें बाबेगैस प्लांट, पवन चिक्कियां, ब्र्डुआरिंकि चूल्हे, ग्राम्य श्रीचालय, सौर साधित्र, कृषि उपकरण इत्यादि शामिल हैं। ये संस्थान अनेक सरकारी और गैर सरकारी एजेसियों से सम्पर्क और प्रमावी सहयोग व समन्वय स्थापित करने में सक्षम रहे हैं। इनमें से अनेक संस्थान सामुदायिक सहायता सेवाओं की आयोजना और कार्यान्यन में सिक्रय रूप से संलग्न हैं। उवाहरण के लिए सामुदायिक बायांगैस प्रणाली, सामुदायिक कचरा निकासी

प्रणाली और जल विषयक ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं, स्वास्थ्य और स्वन्छता जागरूकता कार्यक्रम।

इस योजना में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को तकनौकी प्रशिक्षण दक्षताएं प्रदान करने की प्रबल संमाध्यता है और आठवीं योजना अविध के दौरान इन सुविधाओं को अनुसूचित जाति/अनु० जनजाति, विशेषकर इनकी सघनता वाले क्षेत्रों में प्रदान करने के लिए आवश्यक प्रयास किए जा रहे हैं। ये संस्थान विशिष्ट लक्ष्य समूहों से सभी प्रमुख कार्यक्रम क्षेत्रों में क्रियाकलाप करते हैं। नामतः स्कूल छोड़ने वालों, बालिकाओ और निराम्नित महिलाओं, ग्रामीण कारीगरों और दस्तकारों के लिए।

इस योजना के जनशक्ति विकास और प्रशिक्षण घटक के अन्तर्गत प्रत्येक सी०पी० अनेक दक्षता प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाता आ रहा है। जनशक्ति विकास एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाता आ रहा है। जनशक्ति विकास एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत विमिन्न व्यापार शाखाओं में एक वर्ष में लगमग 300 से 400 उम्मीदवारों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है जिसके परिणामस्वरूप पारिश्रमिक और स्व रोजगार तथा बढ़ी हुई उत्पादक क्षमताओं को बदाया मिला है। परियोजना ग्रामों में अनुसूचित जात/जनजाति के उम्मीदवारों/ग्रामीण युवकों को इन पाठयक्रमों के वाखिल में ग्राथमिकता दी जाती है। इन पाठयक्रमों में वाखिल किए गए लगमग 20% उम्मीदवार अनुसूचित जाति/जनजाति के उम्मीदवारों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। सामुदायिक पालिटिक्नकों द्वारा योग्य अनुसूचित जाति/जनजाति के उम्मीदवारों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। सामुदायिक पालिटिक्नकों द्वारा योग्य अनुसूचित जाति/जनजाति के उम्मीदवारों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम कार्यक्रम साम्वान कन जाति के उम्मीदवारों को छोटे व्यापार स्थापित करने के लिए बैंक से मुण प्राप्त करने और पारिश्रमिकोन्मुख रोजगार प्राप्त करने में ययसंसम्ब सहयना दी जाती है।

प्रौषोगिकी कार्यक्रमों के अन्तरण में कम लागत के श्रीवालय एवं घरों, घरों में बिक्ती पहुंचाने और धुआंरिहत चूल्हे जैसी धुविधाएं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रिहायशी क्षेत्रों में प्रवान की जाती है। उनके जीवन स्तर में सुधार लाने के उपायों में सामाजिक, चानिकी, प्रौद शिक्षा, निजी और सामुदायिक स्वास्थ्य शिविर मी शामिल हैं। सी०पी० द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति परिवारों के लाम के लिए तकनीकी और सामुदायिक सहायता सेवाएं प्रदान करने हेतु विशेष कार्यक्रम आरम्म किए गए हैं।

सींऽपीo आयोजित किए जा रहे। सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण के परिणामों को दृष्टिगत रखते हुए अनुसृषित जाति/अनुसृषित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए अलग से चुने गए क्षेत्रों में और दक्षता विकास कार्यक्रमों के आयोजन के प्रयास किए जाते हैं। अनुसृष्टित जाति/अनुसृष्टित जनजाति समुदायों की अधिकता वाले ग्रामों का सीoपीo टारा अलग से पता लगाया जाता है तािक तैयार की गई मास्टर योजना के आधार पर ऐसे ग्रामों का एक आदर्श ग्राम के तौर पर समेकित विकास हो सके। सीoपीo अनुसृष्टित जातियों/जनजातियों पर सर्वेक्षण रिपोर्ट तथा इस योजना के तहत प्रशिक्षित/सहायता प्राप्त अनुसृष्टित जाति/जनजाति के उम्मीदवारों की सूची बनाएगा और उन्हें रोजगार के पर्याप्त अवसर प्रदान करने के लिए आवश्यक सहायता देगा।

पशिष्ट्य प्रशिक्षण: प्रशिष्ट्य अधिनियम, 1961 का संशोधन वर्ष 1973 में किया गया था ताकि इंजीनियरी और प्रौषोगिकी में डिग्री और डिप्लोमा धारकों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा सके। इस योजना के माध्यम से इंजीनियरी कॉलेजों और पॉलिटेक्निकों से नव-उत्तीर्ण उम्मीदवारों को उपयोगी रोजगार/स्व-रोजगार के लिए उद्योग में व्यावहारिक प्रशिक्षण पाने के अवसर प्राप्त होते हैं। प्रशिक्ष प्रशिक्षण की निर्धारित अवधि एक वर्ष है। स्नातक प्रशिक्षार्थियों को 700/- ए० प्रति मांड की दर से और डिप्लोमा धारकों को 500/- रु० प्रति माह की दर से वृत्तिका का भगतान किया जाता है। सान्तराल पाठयक्रम के विद्यार्थियों को भी 500/- रु० प्रति माह (डिग्री धारक) और 400/- रु० प्रति माह (डिप्लोमा धारक) की वृत्तिका का भुगतान किया जाता है। इस समय लगभग 2,300 प्रशिक्षणार्थी है। राज्य सरकार की नीति के अनुसार इंजीनियरी कॉलेजों और पॉलिटेक्निकों के दाखिले में अनुसचित जातियों और जनजातियों को नियमानुसार क्रमश: 15% प्रतिशत और 7.5 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया जाता है। प्रशिक्ष प्रशिक्षण बोर्ड अनसचित जाति/जनजाति के सभी आवेदकों को प्रशिक्षण सविधाएं प्रदान करने के विशेष प्रयास करते हैं चाहे आवेदकों की संख्या इन समदायों के लिए निर्धारित कोटे से भी अधिक हो। प्रशिक्ष प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत उम्मीदवारों का चयन औद्योगिक संगठनों/संस्थाओं द्वारा किया जाता है और उन्हें इस योजना के अन्तर्गत आवेदन करने वाले सभी अनसचित जाति/जनजाति आवेदकों का चयन सनिश्चित करने के लिए आवश्यक अनुदेश दिए जाते हैं।

भारतीय पौद्योगिकी संस्थान: भारपी०सँ० सहित विभिन्न तकनीकी शैक्षिक संस्थानों में अनुसूचित जाति/जनजाति के दाखिले की स्थिति में सुभार लाने के लिए भारपी०सँ० परिषद ने अपनी 28वीं बैठक में कुछ सिफारिशों की है। इनमें से प्रमुख निम्नानुसार है: (i) प्रतिभाशाली और मेघावी अनुसूचित जाति/जनजाति के विद्यार्थियों का चयन स्कूल स्तर पर किया जाना चाहिए और XI और XII कलाओं (तन्यश्चान IX से XIIवीं कक्षाओं) के विद्यार्थियों के लिए विशेष कोचिम कक्षाओं का अयोजन किया जाना चाहिए लांकि उन्हें इंजीनियरी, मैडिसिन, इत्यादि के व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए अन्य विद्यार्थियों के साथ प्रतिस्पर्यन्मक होने के लिए तैयार किया जा सके।

(ii) स्कूली कार्य घंटों के पश्चात चुनिन्दा केन्द्रीय विद्यालयों (आगम्भ में 60 से 80 स्कूलों में) में विशेष कोचिंग कताओं का आयोजन किया जाना चाहिए। केन्द्रीय विद्यालयों में इस प्रकार की विशेष कोचिंग कताओं के आयोजन की अनुमानित लागत का परिकलन राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंघान एवं प्रशिक्षण परिषद्ध द्वारा किया जा सकता है। मानव संसाधन विकास मैत्रालय केन्द्रीय विद्यालय संगठन के परामर्श से इस प्रकार के कोचिंग कार्यक्रमों के लिए केन्द्रीय विद्यालयों का चयन कर सकता है।

पारिम्मक पाठ्यक्रम : प्रारम्मिक पाठ्यक्रम 1983 से मारतीय प्रोद्योगिकी संस्थानों में शुरू किए गए हैं। संयुक्त प्रवेश परीक्षा में बैठने वाले अनुसुचित जाति/अनुसुचित जनजाति के कुछ उम्मीदवारों को एक वर्षीय प्रारम्मिक पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया जाता है। ऐसे परीक्षार्थी जो संयुक्त प्रवेश परीक्षा की श्रेष्ठता सुची में आने में असफल रहते हैं, उन पर एक वर्षीय प्रारम्मिक पाठ्यक्रम की विद्यार्थियों की सुची में शामिल करने के लिए विचार किया जाता है। इस पाठ्यक्रम में मौतिक विज्ञान, रसायन शास्त्र, गणित और अंग्रेजी में प्रतिविषय पित सप्ताह 5 घण्टे के आधार पर गहन अनुदेश प्रदान किए जाते हैं। ऐसे विद्यार्थी जो प्रारम्भिक पाठ्यक्रम के अन्त में प्रत्येक विषय में 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करते हैं, उन्हें आगामी वर्षों में नियमित कार्यक्रम में प्रवेश दे दिया जाता है। हालांकि, औक्षिक निष्पादन के विक्लेपण से यह या चला है कि प्रारम्भिक पाठ्यक्रम के प्रवेश के माध्यम से अलेप हुए विद्यार्थी संयुक्त प्रवेश परीक्षा के माध्यम से अल्प हुए विद्यार्थी संयुक्त प्रवेश परीक्षा के माध्यम से जाते हैं।

मारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा ली जाने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा 1995 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को निम्नलिखित सुविधायें दी जा रही हैं:—

- (i) अनुसूचित जाति के लिए पन्दह प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति के लिए 7.5 प्रतिशत स्थान आरक्षित हैं। मारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली में अनुसूचित जाति के लिए पन्दह और अनुसूचित जनजाति के लिए 22 स्थान उपलब्ध हैं।
- (ii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए अर्डता मानदण्डों में छूट दी गई है।
- (iii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विद्यापियों के लिए पंजीकरण शुल्क सिंहत आवेदन प्रपन्न की कीमत कम है, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विद्यापियों के लिए यह 125/- रुठ है जनकि सामान्य भ्रेणी के विद्यापियों के लिए यह 300/- रुठ है।
- (iv) परामर्श के लिए बुलाये गये अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को उनके स्थानीय निवास स्थान से भारतीय ग्रीद्योगिकी संस्थान तक लायुतम मार्ग से आने और जाने का दितीय स्रेणी का रेल का किराया दिया जाता है।
- (v) उन्हें उनके सामान्य निवास स्थान से उस संस्थान तक जहां उन्हें प्रवेश दिया गया है का लघुतम मार्ग से गेन का दिनीय श्रेणी का किराया भी दिया जाना है। हालांकि इस किराये का भूगतन उनके संस्थान में शाने के बाद ही किया जाता है।
- (vi) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय और आई०टी० बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में प्रवेश पत्र प्राप्त अनुसूचिन जाति/अनुसूचिन जनजाति के सभी विद्यार्थियों की ट्युशन शुल्क का भुगतान नहीं करना होता है। इसके अतिरित्त, बी०टेक०/इनटेक एम०एस सी उनटेक एम०टेक० में अध्ययनरत अनुसूचित जाति/अनुसूचिन जनजाति के सभी विद्यार्थियों की निःशुल्क भोजनालय (श्रृनियादी मीन् केवल) की सुविधा मी दी जाती है। सुतिमाह 70/- रा० का जेब खर्च मैटिकांतर छात्रदात पदान करने के लिए समय-समय पर निर्धारित की गई अभिमादकों की न्युनतम याय सीमा पर निर्मार करता है।
- (vii) अनुभूजिन जाति/अनुभूजिन जनजाति के ऐसे विद्यार्थियों को. जे संयुक्त प्रवेश परीक्षा में अपनी योग्यता के आधार पर स्नानक पाठयक्रमों में प्रवेश प्राप्त नहीं कर पाने हैं. एक वर्षीय प्रार्थिभक्ष पाठयक्रम में प्रवेश दिया जाना है जा स्थानों की उपलब्धना और स्युन्तम मानदण्डों पर विद्यार्थियों की सफलना पर निर्मर करना है। ऐसे सभी विद्यार्थी, जो प्रार्थिभक्ष पाठयक्रम सफलतापूर्वक पूरा कर लेते हैं. उन्हें संयुक्त प्रवेश परीक्षा 1996 में पुनः बैठे बिना ही अवर स्नातक पाठयक्रम के प्रयम वर्ष में पृतः बैठे विना ही अवर स्नातक पाठयक्रम के प्रयम वर्ष में पृत्रेश मिल जाता है। प्रारम्भिक पाठयक्रम के ऐसे सभी विद्यार्थियों के निःशुक्क मोजनालय (बुनियार्थी मीनू केवल) की सुविधा प्रदान की जाती है और प्रतिमाह 70/- रुठ का जेब सर्च उपर्युक्त पा में दिए गए उसी मानदण्ड पर निर्मर करना है।

- (viii) प्रत्येक सत्र के लिए सुसमृद पुस्तकालय के पुस्तक बैंक से सभी सम्बन्धित विषयों पर पुस्तकें प्राप्त करने के लिए विशेष सुविधायें निःशुएक प्रदान की जाती हैं। कुछ मारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के व्यापक उपयोग के लिए विशेष पुस्तक बैंक हैं।
- (ix) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के परीक्षार्थियों की शैक्षिक प्रगति का ध्यान रखने के लिए संकाय सलाहकार की विशेष रूप से नियुक्ति की जाती है।

विश्रोष प्रशिक्षण: भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में प्रवेश प्राप्त करने के पश्चात, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के ऐसे विद्यार्थियों को. जो जीक्षक दृष्टि से पिछड़ जाते हैं: उन्हें सम्बन्धित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान उनकी थाग्यता में सुधार लाने के लिए विश्रोप प्रणिक्षण प्रदान करते हैं। इस विश्रोप प्रणिक्षण की प्रमुख विश्रोपताये निम्नलिस्ति हैं:—

- (i) ऐसे विद्यार्थी जो किसी सन्न में विशिष्ट श्रंक प्राप्त करने में असफल रहते हैं उनका पता लगाया जाता है और घतिष्ठ व्यक्तिगत सम्पर्क के माध्यम से उनकी शैक्षिक प्रगति का अनुविक्षण किया जाता है। ऐसे सभी विद्यार्थियों को सन्न के शैक्षिक ब्रोह्म की कम करने की सलाह दी जानी है।
- (ii) चयानत क्षेत्रों के ऐसे विद्यार्थियों को पृथक शिक्षण प्रकार के उपचारात्मक पाठ्यक्रम उपलब्ध कराये जाते हैं और ऐसे पाठ्यक्रम सामान्य क्रोडिट के खाधे होते हैं। अन्य शैक्षिक अक्षमताओं को हुए करने के लिए गर्मियों की छुट्टियों के दौरान कृत्य वानवादी और कार पाठ्यक्रम पढ़ाये जाने हैं नािक वे नियमित सब के होरान शैक्षिक बोझ को कम कर सके।
- (iii) संकाय सदस्यों की समय-सारिणी में एक घण्टे के स्लाट का प्राथधान है लांक वे शैक्षिक दृष्टि से पिछादे विद्यार्थियों और अनुसूचित जांति अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों से उन्हें उपयुक्त, मार्ग दर्शन प्रदान करने के लिए वैयन्तिक रूप से मिला सकें।

ओद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई०टी०आई०)

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हो। औद्योगिक प्रणितण संस्थाना में प्रवेश और स्थापना में प्रणिश्चतावृत्ति प्रणिक्षण के लिए सम्बन्धित राज्यो/सेच शासित क्षेत्रों में उनकी जनसंख्या के अनुपात में भारक्षण प्रदान किया जाता है। प्रशिक्ष्तावृत्ति और औद्योगिक प्रशिक्षण के लिए अनुसचित जाति/अनुसूचित जनजाति है लिए क्षमशः 1.87 और 3.89 लाख स्थान है।

V. प्रौह शिक्षा

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन (एन०एन०एम०) : राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरूआत 1988 में हुई थी। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का लक्ष्य कार्यसाधक साक्षरता प्रदान करना है, जो संगठन और विकास की प्रक्रिया में माग लेकर उनके जमाव के कारणों और उनकी परिस्थितियों को समाप्त करने के लिए उन्हें जगरूक करता है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का दृष्टिकोण राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की मुख्य नीति को तैयार करना और सार्वभौमिक साक्षरता के लक्ष्य को प्राप्त करना है। ये अभियान क्षेत्र केन्द्रित, समयबद्ध स्वैच्छिक संगठन पर आधारित लागत प्रमावी और परिणामोन्मुखी होते हैं।

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का घ्यान ग्रामीण क्षेत्रों, विशेषकर अनुसृचित जाति और अनुसृचित जनजाति के समुदायों की महिलाओं और लोगों पर होता है। तद्दुसार, सम्पूर्ण साक्षरता अभियान का लक्ष्य, सामान्यतया इन समुद्रां के लोगों को शामिल करना है। उन पर विशेष घ्यान दिया गया है और यह कार्यक्रम उनकी महसूस को जा रही आवश्यकताओं के अनुरूप कार्यक्रम मी है। जिला साक्षरता समितियों तथा राज्य संसाधन केन्द्रों ने द्दन समुद्रायों के लोगों के लिए विशेष प्रवेशिकाएं प्रकाशित की हैं। सम्पूर्ण साक्षरता अमियान में यह सुनिश्चित किया गया है कि 9—14 वर्ष की आयु समृद्र के बच्चों के बिल्कुल अनदेखा न किया गया है कि 9—14 वर्ष की आयु समृद्र के अर्घ्यां में एक उपकायक्रम में सम्पूर्ण साक्षरता अमियानों में, 9—14 वर्ष की आयु समृद्र के बच्चों के लिए एक उपकायक्रम होता है। इन बच्चों के लिए नीति, कार्यप्रणाली और प्रदित बिल्कुल अलग होता है। इन बच्चों के लिए नीति, कार्यप्रणाली और प्रदित बिल्कुल अलग होती है। जैसे ही बच्चे सम्पूर्ण साक्षरता अमियानों के अन्तर्गत प्रथम चरण पूरा कर लेते हैं उन्हें अनीपचारिक क्षेत्र में स्थानान्तरित कर दिया जाता है जहां उन्हें इस कार्यक्रम के अन्तर्गत शेष तीन सन्न पूरे करने होते हैं।

राष्ट्रीय साक्षणता मिशन का लक्ष्य 8वीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक 15—35 वर्ष की आयु समूह के 100 मिलियन निरक्षरों को शामिल करना है। अब तक 121 मिलियन सीखने वाले (इसमें ऐसी नव संस्वीकृत परियोजनाओं के नवसाक्षरों की प्रस्तावित संख्या शामिल है वहां सर्वेक्षण नहीं कराया गया है) साक्षरता अभियानों के अन्तर्गत शामिल किए जा रहे हैं। इसमें 15—35 वर्ष की आयु समृह से बाहर के सीखने वालों की संख्या मी शामिल है।

कुछ जिलों से प्राप्त रिपोर्टी के आधार पर, यह अनुमान लगाया गया है कि सीखने बालों में से 38 प्रतिशत पुरुष और 62 प्रतिशत महिलायें हैं। इनमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सीखने वाले क्रमश: 21 प्रतिशत और 10 प्रतिशत हैं।

राप्टांय साक्षरता मिशन ने 8 राज्यों में स्थित 26 जनजातीय जिलों (ऐसे जिले जिनकी कुल आबादी में 40 प्रतिशत या इससे अधिक जनजाति के लोग है, जनजाति जिले माने गए हैं) में माक्षरता अभियानों को संस्थीकृति दी है। ये 8 राज्य हैं : असम , जिहार गुजरात . हिमाचल प्रदेश मध्य प्रदेश . उड़ीसा . राजस्थान , विपुरा और दादरा और नगर हवेली के संघ शासित क्षेत्र। कुछ जनजातीय जिलों, जैसे बिहार में दुमका . हिमाचल प्रदेश में स्वान्दीर मध्य प्रदेश में रायगढ़ . उड़ीसा में सुन्दरगढ़ और राजस्थान में दुर्गापुर, ने साक्षरता चरण के अन्तर्शत चन्छे कार्य-निष्यादन की रिपोर्ट भेजी हैं। उड़ीसा में केनझर का कार्य भी सामान्य है। शेष जिले अभियान के प्रारम्भिक स्वरूप पर है।

जिन जिलों में सकल साक्षरता अभियान पूर्ण हो बुका है वहां उत्तर माक्षरता अभियान चलाए जायेंगे। यह विशेष रूप से अनुसूचित जात/अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों पर लागू होता है ताकि उत्तर साक्षरता व ममुदाय शिक्षा की सुविधायें प्रौढ़ नव साक्षरों को उपलब्ध कराई जा सकें। सकल साक्षरता अभियान/उत्तर साक्षरता अभियानों को प्रति शिक्षु 165/-60 की लागत से निधियां प्रदान की जाती हैं जो केन्द्रीय व राज्य सरकारों के शिव 2:1 अनुपात से पूरा किया जाता है। आदिवासी उपयोजना के अन्तर्गत आने वाले जिलों के सामले में वित्तर्पोषण केन्द्रीय व राज्य सरकार के बीच 4:1 के अनुपात से डोगा।

VI. महिलाओं के अधिकार

मिहला सामाख्या: महिला सामाख्या का मूल उद्देश्य शिक्षा द्वारा मिहलाओं को अधिकार देना है। यह कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में चलाया जाएगा तथा कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य ग्रामीण मिहलाओं. विशेष रूप से समाज के वैचित वर्गों एवं अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को संयटित करना है। यह कार्यक्रम उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक व आन्ध्र प्रदेश के 15 जिलों में विवासन है तथा इसमें ग्रामीण स्तर पर 'संघ' नाम से पुकारे जाने वाले महिलाओं के समूहों को तैयार करने में विशेष सफलता ग्राप्त की है। इस कार्यक्रम में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की महिलासे में माग लेती है तथा पानी, स्वास्थ्य, आर्थिक कार्यक्रलाप व सामाजिक हिसा जैसे मामलों को सल्हाती है।

VII. खात्रवृत्तियां

(i) सामान्य श्रेणी

कुल:

ग्रामीण क्षेत्रों के उत्कृष्ट छात्रों के लिए माध्यमिक स्तर पर छात्रवृत्ति योजना: यह योजना 1971-72 से कार्यान्यित को जा रही है। योजना का उद्देश्य समान शैक्षिक अवसरों को प्राप्त करना तथा ग्रामीण क्षेत्रों के उत्कृष्ट बच्चों को अच्छे स्कृतों में पढ़ाकर उनमें अन्तर्निहित उत्कृष्टता के विकास को प्रोत्साहित करना है। यह योजना राज्य सरकारों/संघशासित प्रशासनों हारा कार्यान्वित की जा रही है। छात्रवृत्तियों का वितरण प्रत्येक राज्य/संघशासित प्रदेश में समुदाय विकास ब्लॉक के आधार पर किया जान है। छात्रवृत्तियों माध्यमिक स्कृत स्तर (कक्षा VI/VII) के जन्त में दी जाती है तथा शिक्षा के + 2 स्तर सहित माध्यमिक स्तर तक जारी रहती है और जिस स्तर पर उत्तर मैटिक शिक्षा के लिए भारत सरकार को राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना आरम्म होती है। छात्रवृत्ति योजना आरम्म होती है। उत्तर्ग का चयन राज्येलजजप्रकण्य को सहायता से राज्य सरकारों व संघशामित प्रशासनों हारा किया जाता है। छात्रवृत्तियों की दों 30/- राज्य होगी। प्रति वर्ष 43,000 पुरुस्कारों का क्रेणीवार वितरण निम्न अनुसार है:—

		खात्रवृत्तिया (4×5000)
(ii)	मूमिद्दीन श्रमिकों के बच्चे	प्रति समुदाय विकास ब्लॉक 2 10,000 छात्रवृत्तियां (2×5000)
(iii)	अनुसूचित जाति के अच्चे	प्रति समुदाय विकास ब्लॉक 2 11,500 छात्रवृत्तियां (2×5000) तथा 20% या अधिक अनुसूचिन जाति की जनसंख्या वाले प्रति समुदाय ब्लॉक के लिए एक छात्रवृत्ति (1×1500)
(iv)	अनुसूचित जनजाति	प्रति आदिवासीय समुदाय 1,500 विकास ब्लॉक के लिए 3 छात्रवन्तियां (3×500)

प्रति समदाय विकास ब्लॉक 4 20,000

VIII. भाषाऐ

- बिसेन हार्न मारिया गुतोब, अदि, मोन्या, अनल, माओ, पेत, मार, कार नीकोबारेस, करबी, दिमासा, नोक्टे माषाओं में माषा विषयक वर्णन (व्याकरण व शब्दकोष)।
- हिमाचल प्रदेश की पहाड़ी भाषा पर सर्वेक्षण।
- —आदिवासी भाषाओं में सन्दर्भ सामग्री।
- आदिवासीय बच्चों के लिए द्विभाषीय शिक्षा।
- उत्तर पूर्वी भाषाओं में प्रौद साक्षरता के लिए द्विसाक्षर प्राईमर तैयार करना।
- चुनी हुई आदिवासीय भाषाओं में विश्वकोष (बोड़ो, खासी, सन्तर्ली:गोंडी)।
- कुछ चुनी हुई नागा भाषाओं में स्कूल व्याकरण।
- आदिवासीय भाषाची के चध्यापकों के लिए प्रशिक्षण व सामग्री निर्माण चादि।

IX. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद् अनौपचारिक शिक्षा अनुस्वित जानि व अनुस्वित जनति शिक्षा विभाग, राज्य शैक्षिक अनुसंघान परिषद, विशा प्रौद्योगिकी व शिक्षा सम्थानों के माध्यम सं राज्य व संघशासित प्रदेशों को शैक्षिक एवं तकनीकी संसाधन सहायता प्रवात करने के लिए राष्ट्रीय स्नर की संसाधन सहायता एशेसी के रूप में मूनिक। निमाती हैं तथा इसके साथ-साथ अनौपचारिक शिक्षा व अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की शिक्षा के क्षेत्र में उन स्वैच्छिक एजेंसियों को सहायता देती है।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंघान प्रशिक्षण परिषद ने अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के छात्रों की शिक्षा के लिए निम्मिलियत कार्यक्रम नैयार किए है:—

- अनुसूचित जाति के शैक्षिक विकास की टीका संदर्भिका तैयार करना:
- अनुसुचित जाति के लोगों के दृष्टिकाण से आपितजनक सामग्री का पता लगाकर उसकी अध्यापन अध्ययन सामग्री का विश्लोपण करना:
- अनुसूचित जातियों के विकयात ध्यक्तियों की जीवनी पर पठन सामग्री तैयार करना:
- अनुसूचित जाति के शैक्षिक विकास में रुकावटें पैटा करने वाली समस्याओं का समाधान करने के लिए मुख्य व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण सामग्री का विकास करना:
- क्षंत्रीय भाषा लिपि का प्रयोग करते हुए आदिवासी बोलियों व भाषाओं में अध्यापन अध्ययन सामग्री का विकास करना;

43,000

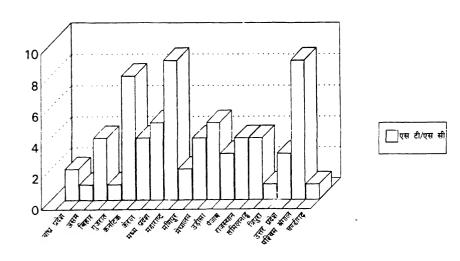
- आदिवासीय भाषाओं में पाठ्य पुस्तकें तैयार करना:
- आदिवासी क्षेत्रों में स्थित माध्यमिक शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों के शिक्षक शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण पाठयक्रमः
- अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की शिक्षा की प्रौन्ति के लिए नितियां तैयार करने के लिए प्रबोधन कार्यक्रम व कार्यशालायें:

हुन कार्यक्रमों के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान व उत्तर प्रदेश राज्यों में कहा I से VIII के लिए निर्देशात्मक सामग्री का विश्वलेषण किया जा चुका है। अन्य राज्यों की अध्यापन अध्ययन सामग्री का विश्वलेषण कार्य भी प्रगति पर है। डॉं अम्बेडकर के श्रीक्षक विचारों पर विनिबन्ध व अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय के अन्य नेताओं की टीका संदर्भिका भी निकाली गई है।

अनुसूचित जनजाति की अध्ययन आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से विभिन्न आदिवासी भाषाओं में सामग्री विकसित की गई है।

केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर व सी०आई०ई०एफ०एल० डैदराबाद के सहयोग से आंध्र प्रदेश के गोंडा, तमिलनाडु के इरूल तथा बिहार की पांच आदिवासी भाषाओं अर्थात हो. संतल, मुंडगें। खरिया व कुरस्व में ग्राईमर तथा अरुणाचल प्रदेश के आदिवासी छात्रों अर्थात मोन्या. अदि, साम्ती और निशिंग में ग्राईमर त्रिकसित किए गए हैं। 'मीट आवर टाईबल पीपला' के अन्तर्गत अनुपुरक सामग्री तैयार की जा रही है। ये सामग्री आदिवासी समुदाय के जीवन, संस्कृति व पर्यावरणिक परिस्थितियों की ओर घ्यान आकर्षित करनी है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों को प्रदान की गई राष्ट्रीय प्रतिभा योजना स्वित्ववित्यां 1994-95

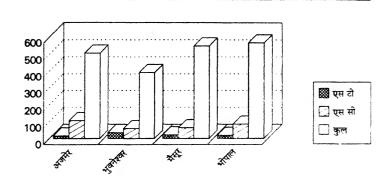


चित्र VII

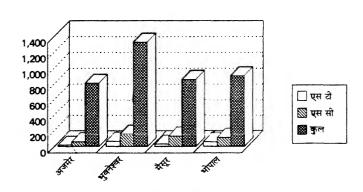
अनीपचारिक शिक्षा केन्द्रों में आनन्ददायक कार्यकागायों की शुरू करके अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से आने वाले शिक्षुत्रों की भागीदारी के स्तर को सुधारने के लिहाज से जनजातीय क्षेत्रों में कार्य कर रहे शिक्षकों के प्रशिक्षण तथा जनजातीय शिक्षा में राज्य/जिला स्तर के कार्यकर्ताओं के लिए प्रबोधन पाठयक्रमों को शुरू किया जा रहा है। राष्ट्रीय प्रतिभा खोज योजना : राष्ट्रीय प्रतिमा खोज योजना के अन्तर्गत दसवीं कक्षा के अन्त में प्रतिमावान विद्यार्थियों का पता लगाकर उन्हें अन्त्री शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है ताकि उनकी प्रतिमा और अधिक विकसित हो सके और वे सम्बन्धित क्षेत्रों में देश की सम्पत्ति बन सकें। राष्ट्रीय प्रतिमा खोज योजना के अन्तर्गत प्रतिवर्ष 2 स्तरों पर परीक्षाओं के आधार पर 750 विद्यार्थी खात्रवृत्तियां प्रदान करने के लिए चुने जाते हैं।

वर्ष 1963 में राष्ट्रीय प्रतिमा खोज योजना के प्रारम्भ होने से लेकर वर्ष 1980 तक राष्ट्रीय प्रतिमा छात्रवृत्तियां पूर्णतया योग्यता के आधार पर प्रदान की गई। वर्ष 1980 में अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्षियों के लिए अर्डक अंकों में 20% की छूट की अनुमति देकर 50 अतिरिक्त छात्रवृत्तियां स्वीकृत की गई। यह उस समय की 500 छात्रवृत्तियों के अतिरिक्त खीं। यह 50 छात्रवृत्तियां विशिष्ट रूप से अनुसुचित जाति/जनजाति अभ्यर्षियों के िलए थी. जबकि अधिक अंक प्राप्त करने वाले अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थी 500 छात्रवृत्तियों में मी शामिल थे। वर्ष 1983 में छात्रवृत्तियों की संख्या 550 से बढ़ाकर 750 कर दी गई। 200 छात्रवृत्तियां बढ़ने के आधार पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए छात्रवृत्तियां और बढ़ा दी गई। इस समय अनुसूचित जाति/जनजाति सहित सामान्य श्रेणी में 680 छात्रवृत्तियां हैं तथा 70 छात्रवृत्तियां विशेष रूप से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए छात्रवृत्तियों में 500:50 से 680:70 तक की वृद्धि हुई है।)

वर्ष 1994-95 के दौरान क्षेत्रीय शिक्षा संस्थानों / क्षेत्रीय शिक्षा कालेजों में सेवा पूर्व पाठ्यक्रमों में दाखिला



वर्ष 1994-95 के दौरान डी॰ एम॰ एस॰ में दाखिला



चित्र VIII & IX

वर्ष 1994-95 के दौरान राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिपद द्वारा प्राप्त छात्रवृत्तियों की संख्या का विवरण संलग्नक-VII में दिया गया है।

क्षेत्रीय शिक्षा कालेज: २१० शै० ३० ४० ४० ४० के मुख्य कार्यों में से एक मुख्य कार्य सेवा-पूर्व शिक्षक शिक्षा के नये कार्यक्रम विकसित करना है। क्षेत्रीय शिक्षा कालेज, स्कूल शिक्षा तथा शिक्षक शिक्षा के विमिन्न पहलुओं से संबंधित अनुसंधान अध्ययन. शिक्षक शिक्षकों, शिक्षकों तथा शिक्षक पशिक्षकों के प्रयोग के लिए शिक्षा सामग्री का विकास तथा स्कूली शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए प्रशिक्षण तथा विस्तार कार्यकलायों में लगे हुए हैं।

प्रत्येक क्षेत्रीय शिक्षा कालेज अपने अधिकार क्षेत्र में राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की शैक्षिक आवश्याकताओं को पूरा करता है। अनुमृषित जाति/अनुष्टुष्टित जनजाति अन्यर्थियों के प्रतिवेदन सहित सभी पाठ्यक्रमों में प्रवेश योग्यता के आधार पर दिया जाता है। नामांकन संख्या से यह पता चलता है कि वर्ष 1993-94 के दौरान सभी चार क्षेत्रीय शिक्षा कालेजों में संखा पूर्व पाठ्यकमों में 309 अनुसृष्टित जाति तथा 92 अनुसृष्टित जनजाति विचार्थियों को प्रवेश दिया गया है जो कि कुल नामांकन का क्रमश: 14.38 तथा 4.58 प्रतिशत है। वर्ष 1994-95 के दौरान क्षेत्रीय शिक्षा कालेजों में विमान्न पाठ्यक्रमों में विचार्थियों के नामांकन का विचरण संलग्न VIII एवं यिन तथा अकृति VIII एवं यि से में दिया गया है।

X राष्ट्रीय शिक्षा योजना एवं प्रशासन संस्थान (नीपा)

अनुसूचित जाति/अमुसूचित जनजातियों का शैक्षिक विकास करना सातवीं पेचवर्षीय योजना से नीपा के कार्यक्षेत्र का मुख्य विषय रहा है। नीपा ने अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक कार्यक्रमों तथा योजनाओं से संबंधित कई अध्ययन किए हैं। यह अनुसूचित जाति/जनजाति के शैक्षिक विकास से संबंधित सामग्री को भी तैयार कर रहा है। यह सामग्री संस्थान के लगमग सभी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रयोग की जा रही है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विकास से संबंधित कार्य कर रहे आग्रम स्कूलों के विभागाध्यक्षों तथा जिला स्तर के अधिकारियों के लिए नीपा द्वारा वर्ष 1985 से जलग से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा नहें हैं।

वर्ष 1993-94 के लिए आयोजित प्रशिक्षण तथा अनुसंघान कार्यकलायों में "अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों को शिक्षा के समान अवसर" पदान करने में संबंधित कार्यकलायों को शामिल करने पर पूरा स्थान दिया गया है।

वर्ष 1993-94 में नीपा ने इसी प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए। संस्थान आंध प्रदेश सरकार के सहयोग से आंध प्रदेश में जनजातीय स्कूलों के प्रधानाध्यापकों के किए प्रशिक्षण कार्यक्रम को आयोजित करने की योजना बना रहा है। संस्थान को "जनजातीय स्कूलों के प्रधानाध्यापकों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं का मूल्यांकन तथा अनुसूचित जनजातियों का शैक्षिक विकास" विषय पर अध्ययन करने की भी योजना है। खाठवीं पंचवर्षीय योजना है। त्राठवीं पंचवर्षीय योजना के तौरान जिला स्तर पर एक विश्लेषण किया गया।

XI. अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना तथा जनजातीय उप योजना

विशेष घटक योजना तथा जनजातीय उप योजना को सर्वप्रथम पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया। ऐसी योजनाएं जिनके द्वारा अनुसूचित जाति/अनुस्वित जनजातियों को लाम पहुंचाया जा सकता है, योजना का विशिष्ट हिस्सा है। इन योजनाओं में इन समुदायों के लिए संसाधनों को अलग से निर्धारित किया गया है।

विशेष घटक योजना : विशेष घटक योजना इस प्रकार बनाई गई है कि उनुसूचित जातियों के मौतिक तथा वितीय विकास के लिए राज्यों तथा केन्द्रीय मंत्रालयों की योजनाओं में सामान्य क्षेत्रों से लाभ तथा लागत की गति को सुकर बनाया जा सके। इन योजनाओं के द्वारा संघटित आय उत्यादन करने वाले कार्यक्रमों के माध्यम से अनुसूचित जनजातियों के गरीब परिवारों की सहायता की जाती है। ये उनकी मूल आवश्यकताओं जैसे पीने का पानी, आवास स्थान, प्राथमिक स्कूलों की स्थापना, स्वास्थ्य केन्द्रों आदि में सुधार करने के प्रयत्न मी करेंगे ताकि सामाजिक, शैक्षिक तथा अन्य सामुदायिक सेवाओं तक उनकी पहुंच में सुधार लाया जा सके।

प्रत्येक क्षेत्र के अंतर्गत सभी केन्द्रीय मंत्रालयों तथा विभागों में पता लगाई गई योजनाओं, जिनका अनुस्चित जाति के विकास से सीधा संबंध है, के लिए मंत्रालय की योजना की विभाज्य धन राशि से धन राशि अलग रखने का विचार योजना आयोग द्वारा शुरू किया गया था और इसके लिए निम्नलिखित ठोस कदम उठाने का सुझाव दिया गया था:—

- अनुस्चित जाति/जनजातियों के लिए उचित आवश्यकताओं पर आधारित कार्यक्रम बनाना।
- अनुस्चित जातियों/अनुस्चित जनजातियों की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप समी चल रहे कार्यक्रमों को अपनाना।
- केन्द्रीय मंत्रालयों के विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत निष्धियों को निष्परित करना।

जनजातीय उप योजना : जनजातीय उपयोजना एक क्षेत्र विकास योजना है, जिसमें जनजातीय जनसंख्या, जनजातीय व्यक्तियों के शोषण का उन्मूलन तथा शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से मानव संसाधन विकास पर विशेष ध्यान दिया जाता है।

केन्द्रीय मंत्रालयों की मूमिका बहुत कठिन मानी गई है क्योंकि उनके संबंधित क्षेत्रों के विकास में जनजातीय क्षेत्रों तथा जनजातीय लोगों के विकास का उत्तरदायित्व सम्पूर्ण रूप से उन पर है। योजना आयोग के जोर देने पर वर्ष 1971-78 में केन्द्रीय मंत्रालयों तथा विभागों द्वारा जनजातीय क्षेत्रों के लिए पृथक कार्यक्रमों का पता लगाया गया। केन्द्रीय मंत्रालयों ने सभी चालू कार्यक्रमों को अनुसूचित जनजातियों की आवश्यकताओं के अनुसूच बनाया है। जनजातीय क्षेत्रों में अधिक धनराशि तथा जनजातीय क्षेत्रों में अधिक धनराशि तथा जनजातीय क्षेत्रों में अधिक धनराशि तथा जनजातीय क्षेत्रों में अधिक धनराशि को खुंचाने के लिए संबंधित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत अलग से बजट उपशीर्ष अपनाया है।

शिक्षा विमाग पिछले कुछ वर्षों से अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना तथा जनजातीय उप योजना बना रहा है।

सानव संसाधन विकास मंत्रालय, शिक्षा विचाग ने वर्ष 1994-95 की दार्थिक योजना लागत 1549.46 करोड़ रू० है। अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष घटक योजना के अंतर्गत अलग रखी गई धनराशि 102.09 करोड़ रू० है, जनजातीय उप योजना में तदनुरूप आंकड़े 73.60 करोड़ रू० है। यह 705.14 करोड़ रू० की विचाज्य लागत से अलग है। विचाज्य लागत

से विशेष घटक योजना तथा जनजातीय उप योजना के लिए राशि क्रमश: 14.48 प्रतिशत तथा 10.44 प्रतिशत है।

XII. शैक्षिक संस्थाओं में दाखिला और नियुक्ति में आरक्षण

आरक्षण को अवधारणाः शिक्षा जिसे संगठित शिक्षण के रू प में लिया गया है. विकास प्रक्रिया का इंग है। सैदांतिक रूप से शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे कि लोग ज्ञान और आवश्यक कौशल प्राप्त कर सकें। और इस शिक्षा व कौशल से बेहतर व्यावसायिक स्तर या जीवन में उच्च सामाजिक स्तर प्राप्त करने के लिए प्रतिस्मर्धा कर सकें तथा उसे प्राप्त कर सकें। इस प्रकार शिक्षा से व्यक्ति की और उपपरिणाम के रूप में, समाज को सामाजिक और आर्थिक उत्पादकता का मार्ग प्रशस्त होना चाहिए। किसी भी खुले व प्रतियोगी समाज में शिक्षा के बारे में ये कुछेक मान्यताएं हैं। निष्पक्ष प्रतियोगिता के लिए व्यक्ति या उसके समुदाय को प्रभावित करने वाले प्रारंभिक सामाजिक स्तर या परिस्थित में समानता अपेक्षित हैं। अतः उन लोगों के लिए राज्य द्वारा संरक्षण या सहायता प्रदान किए जाने को आवश्यकता है जिन्हें इस प्रकार का प्रारंभिक लाभ उपलब्ध नहीं है या जो सामाजिक और आर्थिक आवश्यकता के शिकार हैं। उन्हें भारतीय समाज का आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से लाभ वंचित समुदाय माना जाता हैं।

संविधान में अनुसृचित जातियों और अनुसृचित जनजातियों की सुरक्षा के लिए विशेष उपायों का प्रावधान है तथा राज्यों को इन वर्गों में शिक्षा को बदाया देने के लिए निर्देश दिया गया है। संवैधानिक निर्देशों के परिप्रेश्य में सरकार द्वारा चलाई जा रही शैक्षिक संस्थाओं में दाखिला और नियुक्ति में आरक्षण सहित अनेक प्रावधान/कार्यक्रम बनाए गए हैं। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण प्रदान करने का अंतिम लह्य है—सामाजिक और आर्थिक इंग्टि से उन्हें उपर उठाना और बराबर के स्वम बनाना।

दाखिला में आरक्षण:

विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षाःअनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के दाखिले के मामले में आरक्षण आदेशों को लागू करने के लिये विश्वपिद्यालय अनुदान आयोग द्वारा केन्द्रीय विश्वविद्यालयों, राज्य सरकारों.संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के शिक्षा सर्विकों को समय-समय पर अनुदेश जारी किए गए हैं।

मौजूरा अनुदेशों के अनुसार, सभी पाठ्यक्रमों में अनुसूचित जातियों के छात्रों के लिए 15% सीटें तथा अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के लियं 7.5% सीटें आरक्षित करना हैं। दोनों ही श्रेणियों के उम्मीदवारों को न्यूनतम अर्हक अंक (यदि कोई हो) में 5% अंक को छूट देनी है। इसके बावजूद भी अगर आरक्षित सीटें भर नहीं पाती हैं तो और भी छूट दो जानी चाहिए तािक सभी सीटें अन्जान/अन्जन्म श्रेणी के छात्रों द्वारा भरी जाएं। केन्द्रीय संस्थाओं में अनुसूचित जाितयों और अनुसूचित जनजाितयों के लिए क्रमशः 15% और 7.5% सीटें आरक्षित को जाती हैं, किन्तु राज्य सरकारों के अधीन ऐसी सीटें राज्य विधानमंडल के अधिनयमों द्वारा अभिशासित होती हैं। आमतौर पर राज्य सरकारें राज्य क्रमे बनसंख्या में अनुसूचित जाितयों और अनुसूचित जातियों के अनुस्कर इन समुदायों के लिए सीटें आरक्षित करती हैं।

नवोदय विद्यालय और केन्द्रीय विद्यालय: नवोदय विद्यालयों में दाखिलों के संबंध में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण संबंधित जिले में उनकी जनसंख्या के अनुपात में दिया जाता है परंतु यह क्रमश: 15% और 7.5% के राष्ट्रीय औसत से कम नहीं होना चाहिए। इस समय इन विद्यालयों में चुने गए कुल छात्रों मे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के छात्रों का प्रतिशत क्रमश: 20.52 प्रतिशत और 11.90 प्रतिशत है। केन्द्रीय विद्यालयों में नए दाखिले का 15% और 7.5% अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बच्चों के लिए आरक्षित हैं।

तकनीकी शिक्षाः भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित इंजीनियरी और तकनीकी संस्थाएं अनुसूचित जातियों के लिए 15% सीटें तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए 7.5% सीटें आरक्षित करती हैं। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, द्वारा अनुमोदित राज्य सरकार की मंम्थाओं को राज्य नीति कं अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण नियमों का पालन करना अपेक्षित होता है।

इंजीनियरी और तकतीकी संस्थाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के छात्रों की संख्या बढ़ाने के लिए भारत सरकार द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं।

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई॰ टी॰ आई॰): संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की जनसंख्या में अनुस्चित जातियों और अनुस्चित जनजातियों के अनुपात के अनुसार इन श्रेणियों के छात्रों को औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों और प्रशिक्ष प्रशिक्षण में टाखिला के लिए सीटें आरक्षित हैं।

चिकित्सा कालेज: राजकीय चिकित्सा कालेजों में दाखिला प्रवेश में योग्यता के आधार पर दिया जाता है।अनुमृचित जातियों और अनुमृचित जनजातियों के छात्रों को निर्धारित प्रतिशत के अनुमार आरक्षण दिया जाता है अर्थात् अनुमृचित जातियों को 15% और अनुमृचित जनजातियों को 7.5%।

इसके अतिरिक्त सभी राज्य सरकारों संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से इस प्रकार के पाठ्यक्रमों में दाखिला के इच्छुक अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के छात्रों की विशेष कोचिंग की सूचित्रागं उपलब्ध कराने के लिए अनुरोध किया गया है।

चिकित्मा और अर्ध-चिकित्मा संस्थाओं में आरक्षण नीति का स्वास्थ्य और परिवार कल्याए। मंत्रालय के नियंत्रणाधीन केन्द्र सरकार की चिकित्सा संस्थाओं में कड़ाई से पालन किया जाता है।

XIII: केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में नियुक्तियों में अनुसूचित बातियों और अनुसूचित बनबातियों के लिए आरक्षण

जैमा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय-समय पर अनुदेशों को दोहराया जाता रहा है, मरकार की नीति यह है कि केन्द्रीय विश्वविद्यालय अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को निम्नलिखित में क्रमशः 15% और 7.5% आरक्षण प्रदान करें:—

(i) लेक्करार के स्वर के शिक्षकों की भर्ती:

किसी भी खाम वर्ष में भरे जाने वाले लेक्चरार के स्तर तक के रिक्षण पदों में 15% पद को अनुसूचित जातियों के लिए तथा 7.5% अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित किया जाना चाहिए।

(ii) शिक्षणेतर कर्मचारियों की भर्ती:

सरकार द्वारा निर्धारित पद्धित के अनुसार सभी शिक्षणेतर पदों पर नियुक्ति में 15% पद को अनुसृचित जातियों के लिए तथा 7.5% पद अनुसृचित जनजातियों के लिए आरक्षित किया जाना चाहिए। यह शिक्षण सीधी भर्ती और पदोन्नित दोनों ही मामलों में लागू हेना चाहिए.

(iii) पाठ्यक्रमों और छात्रावासों में दाखिला:

सभी पात्यक्रमों में दाखिला में 15% सीटें अनुसूचित जातियों के लिए अगरिक्षत होनी चाहिए।

इन श्रेणियों के छात्रों को निर्धारित न्यूनतम अर्हक अंकों (यदि कोई हो) में 5% अंक की छूट दी जानी चाहिए। इसके बावजूद भी अगर आरक्षित सीटें भर न पाएं तो इन छात्रों के योग्यताक्रम के अनुसार और भी छूट दी जानी चाहिए ताकि सभी आरक्षित सीटें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के छात्रों से भरी जाएं।

विश्वविद्यालयों/कालेजों में रोडरों और प्रोफेसरों के पदों पर नियुक्तियों व एदोन्नितयों में आरक्षण नीति लागु नहीं है।

10 केन्द्रीय विश्वविद्यालय हैं जो भारत मरकार द्वारा पूर्णनया विनमोपित हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इगन्) को छोड़कर सभी विश्वविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के माध्यम से अनुदान प्राप्त होता है। इगन् को शिक्षा विभाग द्वारा सीधे निधियों उपलब्ध कराई जा रही हैं।

केन्द्रीय विश्वविद्यालय सांविधिक और स्वासत्तशासी निकाय हैं तथा ये अपने अपने अधिनियमों, परिनियमों और अध्यादेशों में अंतर्निहत प्रावधानों के अनुसार काम कर रहे हैं।

काशी हिंदू विश्वविद्यालय, हैंदराबाद विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, पांडिचेरी विश्वविद्यालय और विश्व भारती द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार वे आस्क्षण आदेशों का पालन कर रहे हैं। अन्य विश्वविद्यालयों के बारे। में स्थित इस प्रकार है:

- (क) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ने सूचित किया है कि नियुन्तियों में अ.जा. अ.ज.जा. के लिए आरक्षण नीति के कार्यान्वयन से संबंधित मामला उनके विद्वत परिषद् के विचाराधीन है।
 - (ख) जामिया मिलिया इस्लामिया विभिन्न पाठयक्रमों में छात्रों के दाखिला और शिक्षणेतर पदों पर भर्ती के लिए आरक्षण नीति का पालन करती है।
 - (ग) दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षणेतर समूह ख, ग और घ पदों के सम्बन्ध में आरक्षण नीति का पालन कर रहा है। शिक्षण पदों में विश्वविद्यालयों/कालेजों में शिक्षक के रूप में अठजाठ/

अ०ज०जा० के उम्मीदवारों की मर्ती के सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाती है:

- (i) लेक्न्करार के पांच पदों में से एक पद आरक्षित है किन्तु जब तक अपेक्षित प्रतिशत तक अ०जा०/अ०ज०जा० के उम्मीदवारों की नियुक्ति नहीं हो जाती, अग्रनीत का यह प्रावचान जारी रहेगा:
- (ii) शिक्षक के पद के आवेदन पत्र में एक ऐसे कालम का प्रावधान कि क्या उम्मीदवार अं०जा०/अं०जं० का है.
- (iii) पद के लिए निर्धारित न्यूनतम अर्डता पूरी करने वाले त्राज्जाo/अ्ञाज्जाज के उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाना;
- (iv) शिक्षण पदों पर भर्ती में अ०जा०/अ०ज०जा० के छात्रों को वरीयता; और
- (v) अठजाठ/अठजठजाठ के ऐसे उम्मीदवारों के चुनं न जाने के कारण चयन समिति द्वारा लिखित में दर्ज किए जाने होते हैं जो पात्रता अपेक्षाओं को पूरा करते हैं।

णिक्षा विभाग और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग केन्द्रीय विश्वविद्यालयों द्वारा आरक्षण नीति के कार्यान्वयन और मानिटरिंग के लिए उत्तरदायी हैं।

सरकार तथा आयोग केन्द्रीय विश्वविद्यालयों द्वारा आरक्षण नीति के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए निम्न कदम उठा रहे हैं:

- (i) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग समय-समय पर विश्वविद्यालयों को निर्देश दे रहा है, वि०अ०आ० अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण के सम्बन्ध में मारत सरकार की नीति का पालन करने विश्वविद्यालयों में छात्रों के दाखिलों के साथ-साथ शिक्षण तथा शिक्षणेतर पदों को मरने के लिए विश्वविद्यालयों को स्मरण करा रहा है।
- (ii) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के हितों की रक्षा के लिए केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में अनु० जातियों/अनु० जनजातियों के प्रकोष्ठ स्थापित किए हैं।
- (iii) केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के रिजस्टारों की आविधक बैठकें केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में आरक्षण नीति के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए आयोजित की जाती हैं।
- (iv) आयोग ने एक मानिटिरंग समिति का भी गठन किया है, जिसमें मानव संसाधन विकास मंत्रालय के प्रतिनिधि शामिल हैं जो केन्द्रीय विश्वविकालयों में विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा अपनाई गई कार्यनीतियों की समीक्षा करते हैं। आयोग ने केन्द्रीय विश्वविद्यालयों सहित विश्वविद्यालयों में अनुसुचित जातियों/अनुसुचित जनजातियों के खात्रों के आरक्षण नीति का

कार्यान्वयन की मानिटरिंग करने का उत्तरदायित्व आयोग के एक सदस्य को सौंपा है।

(ख) कल्याण मंत्रालय

उन बच्चों के लिए मैद्रिक पूर्व खात्रवृत्तियां जिनके माता-िपता सफाई व्यवसायों में लगे हुए हैं:

इस योजना का लक्ष्य वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि शौचालयों की सफाई करने वालों, सफाई कार्य करने वालों के बच्चे जो सफाई, चमड़ा उतारना, ताम्र बनाने सम्बन्धी व्यवसायों से परम्परागत रूप से जुड़े हैं, मैटिक पूर्व शिक्षा प्राप्त कर सकें।

यह योजना 1977-78 के दौरान शुरू की गई थी। इस योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता छात्रवृत्तियों के वितरण के लिए वचनबढ़ तायित्य क्याय के अतिरिक्त 50:50 के आधार पर राज्य सरकारों को प्रदान की जाती है।

यह योजना 1 नवम्बर, 1991 को संशोधित की गई थी अब इस योजना में श्रेणीकृत छात्रवृत्तियों अर्थात् कक्षा I से V तक की कक्षाओं के लिए 25/-हु० प्रति माह, कक्षा VI से VIII तक की कक्षाओं के लिए 40/- रू० प्रति माह और कक्षा IX से X तक की कक्षा में 50/- ए० प्रति माह के साथ कक्षा I से कक्षा X तक के दिवसीय छात्रों के लिए है। इस संशोधित योजना में कक्षा III से कक्षा VIII तक के छात्र जो छात्रावासों में रहते हैं उनके लिए खात्रवति दर 200/- रु० प्रति माह है और कक्षा IX से कक्षा X तक के लाव जो छात्रावासों में रहते हैं, उनके लिए छात्रवृत्ति दर 250/- रूठ प्रति माह है। यह छात्रवत्ति वर्ष में 10 माठ के लिए दिवसीय छात्रों के साथ-साथ छात्रावासों में रहने वाले छात्रों को प्रदान की जाती है। संशोधन से पूर्व यह योजना केवल कक्षा VI से कक्षा X तक के छात्र जो छात्रावासों में रहते हैं. उन्हीं के लिए थी। इस संशोधित योजना में प्रति छात्र 500 -रू प्रति वर्ष का तदर्थ अनुदान देने का भी प्रावधान है चाहे भले ही वह दिवस छात्र हो अथवा छाजाबास में रहने वाला छात्र । पात्रता के लिए 1500/- रू० प्रति माह की आय सीमा 25-2-94 से परी तरह समाप्त कर दी गई है। एक परिवार में एक शिशु की पहले वाली योजना :

- (क) 1 से 8 श्रेणियों के सम्बन्ध में खत्म कर दी गई है परन्तु शर्त यह है कि यदि तीसरा या परवर्ती संतान 1-4-93 के बाद पैदा हुना है तो केवल हो संतानें हैं। पात्र होगी
- (ख) उन्हीं अभिभावकों के दो बच्चों को शामिल करने के लिए श्रेणी 9 और 10 के सम्बन्ध में इसमें छट दी गई है।

इस योजना के अन्तर्गत 1992-93 के दौरान 99254 छात्रों को नया 1993-94 में 1,30,715 छात्रों को शामिल किया गया। 1994-95 के लिए ऐसी उम्मीद है कि 2.09 लाख छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की आएगी।

II. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए मैदिकोत्तर खात्रवृत्तियां:

 मैटिकोत्तर छात्रवृत्ति की योजना सबसे महत्वपूर्ण केन्द्रीय प्रायोजित योजना है जिसका उद्देश्य है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की जा सके ताकि वे मैदिकोत्तर अध्ययन जारी रख सकें। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जानजातियों के सभी हात्र. जिनके माता-पिता/अभिभावक नियमों के अन्तर्गत विहित साधन परीक्षण पूरा कर सकते हैं, किसी भी मान्यताप्राप्त शैक्षिक संस्था में दाखिला मिलने पर खात्रवृत्ति के पात्र हैं। यह योजना भारत सरकार हारा बनाए गए नियमों के अनुसार राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों हारा लागू की जाती है तथा खात्रों को उनके अध्ययन के स्थान का लिहाज किए यिना उस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के माध्यम से खात्रवृत्ति प्रदान की जाती है जहां के वे होते हैं।

यह योजना 1944-45 में अनुसूचित जातियों के छात्रों के लिए मात्र 114 छात्रवृत्तियों और 1948-49 में अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के लिए 89 छात्रवृत्तियों से शुरू की गई थी। 1993-94 के दौरान इन दोनों श्रेणियों के छात्रों के लिए छात्रवृत्तियों की अनुमानित संख्या बदकर 16.75 लाख हो गई।

वर्ष 1993-94

विभिन्न पाठयक्कम समूहों के लिए छात्रवृत्ति की दर्रे तथा उनकी पात्रता के मानदण्ड निम्नवत हैं:—

समृहवार अनुरक्षण मने की दरें

(स० हजार मे)

समूह क. ख. ग.	द	;
	छात्रावासीय छात्र	दिवसीय द्वाप
क ्	. 280	125
स ,	190	125
ग.	190	125
휙.	175	90
इ	115	65

मपृह

पाठयक्रम का मंश्रिप्त विवरण

- (क) 1. बंध्युरुएम्श्यूपस्य सहित् मेहिकन्/इंजीतियरी प्रद्रयक्त स्तर की हिंग्री तथा आयुर्थेदिक युनानीः तिक्रिया तथा होमियोपीयक चिकित्सा पदित में समकक प्रद्रयक्ता.
 - ब्री०एस०सी० (कृषि), बी०वी०एस०सी० तथा उच्च तकनीकी एवं व्यावसायिक अध्ययन जैसी डिग्री और कृषि तथा पश्चिकित्सा में स्नातकीलर पाठ्यक्रम।
- (ख) । भारतीय चिकित्सा विज्ञान में डिप्लोम। स्तरीय पाठ्यक्रम और आयुर्वेदिक, युनानी/तिष्मया तथा होमियोपैथिक विकित्सा पर्दति में समकक्ष पाठ्यक्रम।

- इंजीनियरी, प्रौद्योगिकी वास्तुकला इत्यादि में हिप्लोमा एवं समकक्ष पाठयक्रम।
- (ग) 1. इंजीनियरी पौद्योगिकी, वास्तुकला, चिकित्सा विज्ञान आदि में प्रमाणपत्र पाठयक्रम।
 - कृषि, पश्च चिकित्सा इत्यादि में डिप्लोमा/प्रमाणपत्र पाठयक्रम। सफाई निरीक्षक पाठयक्रम, ग्रामीण सेवा पाठयक्रम, राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा कालेज, नागपुर में उप अधिकारी।
 - बी०एड० आदि जैसे शिक्षक प्रशिक्षण में डिग्री/स्नातकोत्तर डिप्लोम। तथा स्नातकोत्तर पाठयकम।
 - (प) स्नातक स्तर तक सामान्य पाठ्यक्रम (दो वर्ष तथा इससे अधिक)
 - (इ.) 10+2 पदित आदि में कक्षा XI तथा XII । सामान्य स्तर के स्तालक पाठ्यक्रमां का प्रथम वर्ष ।

पात्रता के मानदण्ड

- (i) जिन लागों की मासिक आय 2,000 राज से सधिक है उन्हें कीई लाववृति नहीं दी जाने। हैं। जिन लागों की मासिक आय 1500 राज है वे पूर्ण अमुप्तका भना तथा शुल्क पाप्त करने के हकतर है। जिन लागों की मासिक आय 1500 राज है वे शुल्क तथा अमुप्तका भना का आधा भाग पाने के हकतार हैं ("क" समृद्ध के लाग पूरा अमुप्तका पाप्त करने के हकतार हैं ()।
- (ii) एक ही अधिभावक संरक्षक के केवल वो खात्र/छात्रा इसके पाप है।
- (iii) जो छात्र पूर्णकालिक नौकरी में है वे इसके पात्र नहीं है।

इस योजन। के अन्तर्गत अध्ययन याजा शृतक के लिए 100 - रुठ प्रतिमह ओधपन्य के टेकण। मुरण के लिए 600 रुठ, तथा अन्धे द्वांग्री को 1002- रुठ तथा समृह के स्व च के लिए 75 रुठ तथा समृह इ के लिए 50 रुठ प्रतिमह खर्च दिया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत प्रजाचार पाठ्यक्रमों का अनिवार्य शुल्क भी इसमें आमिल है।

वर्ष 1994-95 के दौरान इस योजना के अन्तर्गत लाभग्राहियां की अनुमानित संख्या 17 लाख से अधिक है।

अनुसूचित जाति/ज्ञभुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को विमान चालन (उड़ान) जैसे व्यावसायिक पाठ्यक्रम जिसका प्रांगक्षण काफी सर्चीला है, में शामिल करने के लिए खाजवृत्तियां प्रदान की जाती हैं। इस पाठ्यक्रम में उन्हें व्यावसायिक विमान चालक लाइसेंस प्रशिक्षण के लिए सभी उड़ान सर्च भी दिया जाता है। इस प्रकार के प्रशिक्षण में खाजवृत्ति पाने वालों की संस्था वर्ष 1994-95 से 15 से बढ़कर 20 हो गई है।

III. अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आदि के बात्रों को विदेशों में उच्च अध्ययन करने के लिए राष्ट्रीय ओवरसीज बात्रवत्तियां

राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्ति योजना एक योजनेतर योजना है। इस योजना के अन्तर्गत अनुसचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों, अन्य धर्मी से धर्म परिवर्तित कर अनुसूचित जातियों अथवा उनके आश्रितों, बंजारों खानाबदोश, अर्घखानाबदोश जनजातियों तथा मूमिहीन खेतिहर मजदरों के बच्चों तथा परम्परागत शिल्पियों के 30 अभ्यर्थी पात्र हैं जिनका प्रतिवर्ष (1991-92 से) चयन कर उन्हें विदेशों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए मेजा जाता है। उन्हें पी०एच०ही० तथा पोस्ट हॉक्टोरल अनुसंघान/प्रशिक्षण के लिए छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं। विशिष्ट विषयों में विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा इंजीनियरी अध्ययन, मास्टर हिग्री में वरीयता दी जा रही है। इस समय स्व-चालन नथा रोबोट विज्ञान लेजर प्रौद्योगिकी कागड पौद्योगिकी, नौसेना वास्तुकला/अवतट संरचना, कम्प्यूटर इंजीनियरी/ साफ्टवंयर सहित सूचना प्रौद्योगिकी, वैकल्पिक ऊर्जा/सौर ऊर्जा, दुष्टिमिति, संग्रहालय विज्ञान, पैकेजिंग इंजीनियरी/ प्रौद्योगिकी, गोदी तथा पत्तन इंजीनियरी, औद्योगिक सरक्षा, औद्योगिक वित्त/व्यवसाय, जैव पौद्योगिकी/प्रजनन प्रौद्योगिकी, पेट्रौलियम प्रौद्योगिकी, विमान/अन्तरिक्ष इंजीनियरी तथा नामिकीय इंजीनियरी, तथा मुद्रण प्रौद्योगिकी में स्नातक हिप्री पर त्रिशेष वरीयता दी जा रही है।

न्युनतम अर्हताएं

- (क) पोभ्न डाक्सोरल: मास्टर डिग्री में प्रथम भ्रेणी/60 प्रतिशत अंक (अनुसूचित जनजाति के लिए 50 प्रतिशत अंकों सहित दिनीय भ्रेणी), पी-एच०डी०, अनुसंधान/शिक्षण/व्यावसायिक क्षेत्र में 5 वर्ष का अनुमव।
- (ख) पी-एच॰डी॰ मास्टर डिग्रो में प्रथम श्रेणी/60 प्रतिशत प्रतिशत क्षेत्र (अनुसूचित जनजातियों के लिए 50 प्रतिशत क्षेत्रों सहित दिनीय श्रेणी) शिक्षण/अनुसंधान/व्यवसाय में 2 वर्ष का अनुमन अथवा एम०फिल० हिप्री।
 - (ग) मास्टर डिप्री: बैचलर डिप्री में प्रथम प्रेणी/60 प्रतिशत अंक अथवा लुगदी (पल्प) नथा कागज प्रौद्योगिकी में बी०एस-सी० के पश्चार डिप्लोमा (अनुसूचित जनजातियों के लिए 50 प्रतिशत अंकों सहित दितीय प्रेणी), 2 वर्ष का कार्य अनुभव।
 - (घ) बैकलर डिग्री: मुदण प्रौद्योगिकी में डिण्लोमा/लाइसेंसिएट में प्रथम श्रेणी/60 प्रतिशत अंक (अनुसूचित जनजातियों के लिए 50 प्रतिशत अंकों सहित दितीय श्रेणी, दो वर्ष का कार्य अनुमुख ।

आयु : 35 वर्ष से कम, चयन समिति द्वारा 3 वर्ष की छूट दी जा सकती. है।

आय: प्रतिमाह 5000/- ए० से अधिक न हो।

वैद्यता: अवधि/समयावधि: अभ्यर्थियों का चयन होने पर उन्हें तीन वर्ष के मीतर ही विदेशी संस्थाओं में दाखिला लेना होगा। अध्ययन पूरा होने अथवा अगली अविध जो भी पहले हो उस वक्त तक खात्रवृत्तियां प्रवान की जाती हैं (क) पोस्ट डाक्टोरल : 1½ वर्ष (स) पी-एच०डी० : 4 वर्ष (ग) मास्टर डिग्री : 3 वर्ष (घ) बैचलर डिग्री : 3½ वर्ष।

बात्रवृत्ति की दरें:

अनुरक्षण

(क) बैचलर डिग्री पाठयक्रम 5940/-अमरीकी डालर

(ख) मास्टर डिग्री/पी-एच०डी० 6600/- अमरीकी डालर

(ग) पोस्ट डॉक्टोरल अध्ययन 7700/-अमरीकी डालर

2. **आकस्मिक व्यय**: प्रतिवर्ष 385 अमरीकी हालर तक

पुस्तकों/अनिवार्य सामग्री/अध्ययन दौरा/शोध प्रबन्ध के टंकण तथा जिल्दसाजी के लिए।

 उपकरण भत्ता 1100/- ५० तक आकस्मिक यात्रा खर्च 15/- अमरीकी हालर तक चुनाय खर्च 150/- अमरीकी हालर

- विश्वविद्यालय/संस्थान के सभी अनिवार्य शुल्क, शिक्षण शुल्क तथा प्रवेश शुल्क आदि, तथा स्वैन्छिक स्वास्थ्य/चिकित्सा भीमा ग्रीमियम, यदि कोई हो।
- न्यूनतम मार्ग से आने तथा जाने दोनों तरफ के किफायती श्रेणी का हवाई जहाज के टिकट की कीमत।
- निवास स्थान से निर्धारित बन्दरगाह तक आने-जाने का दितीय ब्रेणी का रेल भाड़ा।

सामान्य शार्ती : एक अमिमावक/संरक्षक का केवल एक ही छात्र इसका पात्र होगा।

यात्रा असुरान: उपर्युक्त योजना के अन्तर्गत छात्रवृत्तियों के अतिरक्त अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/बंजारों, खानाबरोस तथा अर्घ खानाबरोस जाति के केवल उन्हीं छात्रों को प्रति वर्ष 9 यात्रा अनुदान दिया जाता है, जहां यात्रा सर्च देने की व्यवस्था नहीं है। इस योजना के अन्तर्गत जो छात्र विदेशी सरकार/संगठन अथवा किसी अन्य योजना के अन्तर्गत स्नातकोत्तर अध्ययन, अनुसंधान अथवा विदेशी प्रशिक्षण के लिए योगयता (मेरिट) छात्रवृत्ति प्राप्त कर रहे हैं वे इसके पात्र नहीं हैं।

अध्ययों के पास मास्टर हिग्रो होनी चाहिए अथवा कला या विज्ञान विषय होने पर कोई समकक्ष हिग्री होनी चाहिए और इंजीनियरी तथा मेहिकल विषय होने पर कोई वैचलर हिग्री होनी चाहिए।

जिन अध्यर्थियों को किसी अन्य स्रोत से कोई सहायता प्राप्त हो रही है वे यात्रा अनुदान पाने के पात्र नहीं होंगे। प्रति वर्ष 30 राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्तियां तथा 9 यात्रा अनुदान दिए जाते हैं। वर्ष 1993-94 में 30 अर्घ्याधयों को छात्रवृत्तियां प्रदान की गई थीं। वर्ष 1954-55 में इस योजना की शुरूआत से लेकर 31 मार्च, 1995 तक कुल 492 छात्रों को यह छात्रवृत्ति प्रदान की गई है।

IV. खात्रावास

अनुस्चित जाति की लड़कियों के लिए खात्रावास: -- इस योजना के अन्तर्गत, मिडिल तथा माध्यमिक शिक्षा स्तर की कक्षाओं में पदने वाली अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की लडकियों को छात्रावासीय सुविधाएं प्रदान करने की दृष्टि से छात्रावास भवनों के निर्माण तथा वर्तमान छात्रावासों की संख्या में बदोत्तरी करने के लिए राज्य सरकारों (संघ राज्यों को शत-प्रतिशत) 50:50 के आधार पर केन्द्रीय अनुदान दिया जाता है। सम्बन्धित राज्य सरकारों के माध्यम से मौजूदा कात्रावास के भवनों को आवश्यकतानुसार बदाने के लिए स्वैच्छिक एजेंसियों को भी अनुदान दिया जाता है। बशर्ते कुल लागत का 10 प्रतिशत माग संगठन द्वारा वहन किया जाए तथा शेष 90 प्रतिशत भाग का केन्द्रीय तथा राज्य सरकार द्वारा 50 · 50 के आधार पर वहन किया जाए यद्यपि इस योजना के अन्तर्गत भवनों के निर्माण हेतु ही केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है। फिर भी राज्यों/संघ राज्यों को छात्रावासों की टूट-फूट की मरम्मत करने के लिए स्पेशल कम्पोनेंट योजना के अन्तर्गत विशेष केन्द्रीय सहायता का उपयोग करने की अनुमति दी गई है। सामान्य तौर पर इस प्रकार के छात्रावास में कुल 100 सीटें होंगी जिसमें 10 प्रतिशत सीटें ग़ैर-अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के छात्रों के लिए आरक्षित होगी।

इस योजना को ज़ौर अधिक व्यावहारिक बनाने के लिए वर्ष 1994-95 से छाजावासों की निर्माण लागत की अधिकतम मीमा हटा दी गयी है।

आठवीं योजना के दौरान इस योजना का परिष्यय 26.00 करोड़ छठ है। वर्ष 1994-95 में, 7208 सीटों वाले 73 खाजावासों के निर्माण हेत् राज्यों/संघ राज्यों को कुल आवेटन में से 6.20 करोड़ छठ की राशि जारी कर ही गई थी। वर्तमान वित्त वर्ष (1995-96) के लिए 7.00 करोड़ छठ का आवेटन किया गया है।

अनुस्चित जाति के लहकों के लिए खात्रावास:

बालिका खात्रावास योजना के आधार पर, यह योजना वर्ष 1989-90 में आरम्म की गई थी। इस योजना के अन्तर्गत, आठवीं योजना का परिध्यय 33 करोड़ रूठ है। वर्ष 1994-95 में, इस योजना के अन्तर्गत 24,071 सीटों वाले 327 खात्रावासों के निर्माण के लिए 6,20 करोड़ रूठ के बजट आवटन के मुकाबले में 10,00 करोड़ रूठ की राशि जारी की गई थी। वर्ष 1995-96 में इस योजना का परिध्यय 10,00 करोड़ रूठ है।

अनुसचित जनजाति की लडकियों के लिए छात्रावास:

इस योजना के अन्तर्गत मिडिल तथा माध्यमिक स्तर की कहाओं में पदने वाली अनुस्चित जाति/अनुस्चित जनजाति की लहकियों को अग्रावासीय सुविधाएं प्रदान करने की दृष्टि से छात्रावास मवनों के निर्माण नथा वर्तमान छात्रावासों की संख्या बदाने के लिए राज्य सरकारों (संघ राज्यों को शत-प्रतिशत) 50:50 के आधार पर केन्द्रीय अनुदान दिया जाता है। मामान्य तौर पर इस प्रकार के छात्रावासों में कुल 100 सीटें होंगी जिसमें 10 प्रतिशत सीटें गैर-अनुसुचित जनजातियों के लिए आरक्षित होंगी।

वर्ष 1994-95 के दौरान इस योजना के लिए 3.05 करोड़ रूठ का भजट प्रावधान किया गया है। कुल 2.247 क्षमता वाले 42 छात्रावासों के निर्माण/विस्तार हेतु राज्यों/संघ राज्यों को यह राशि जारी कर दी गई

अनुसूचित जनजानियों के लड़कों के लिए छात्रावास :

बालिका ह्यात्रायास योजना के आधार पर ही अनुस्थित जनजातियों के जड़कों के लिए बाल छात्रावासों के निर्माण करने वाले मानदण्डों को अपनाया गया है। वर्ष 1994-95 के दौरान 1911 सीटों वाले 66 छात्रावासों के निर्माण के लिए राज्यों/संघ राज्यों को 3.07 करोड़ छ० की गाँक जारी की गई थी।

V. अनुसूचित जानियों नथा जनजानियों के लिए बुक बैंकों की केन्द्रीय प्रायोजिन योजना :

इस योजना में अनुसूचित जाति अनुसूचित जतजाति के जिन छात्रों को गोस्ट मैट्रिक छात्रचृति की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गति छात्रचृति मिल रही है उन छात्रों के लिए मेट्रिकल (भारतीय चिकित्सा उद्दित/होमियांपैपी सहित), हंगीतियरी (मेरिन इंजीनियरी इलेक्ट्रातिकों आदि सहित), कृषि तथा पशु चिकित्सा हिणी कालेजों नथा पालिटेक्निकों में बुक बैकों की स्थापना की परिकल्पना की गई है। इस योजना के अन्तर्गत गठयक्रम पुस्तकों का प्रत्येक सेट वी छात्रों में विभक्त किया जाता है।

यह योजना राज्य सरकारों, सध राज्य प्रज्ञासनों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है। इस योजना के अन्तरीत राज्यों की समान आधार पर (संघ राज्यों की शत-प्रतिशत आधार पर) केन्द्रीय महायता प्रदान की जाती है बज़र्ने विभिन्न पाठ्यक्रमी के प्रत्येक सेट की लागत तिम्नवत हो :

गर्यक्रम	प्रति सेट अधिकतम लागत	
	(रु० हजार में)	
मेडि क ल	7500 - 1 00	
इंजीनियरी	7500/- to	
पशुचिकित्सा	5000 - Es	
कृषि	4500/- €0	
पॉलिटे क्निक	2400/- ভত	

सामग्री संग्रहण के लिए एक स्टील की अलमारी तथा परिवहन जैसे आकस्मिक व्यय की अधिकतम सीमा 2000/- ठ० ग्रति अलमारी है।

वर्ष 1994-95 में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के 37.877 क्षत्रों को शामिल करने के लिए राज्यों/संघशासित क्षेत्रों को 3.50 करोड़ छ० की केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई। वर्ष 1995-96 के दौरान इस योजना के लिए 3.60 करोड़ छ० का प्रावधान रखा गया है।

VI. शिक्षण एवं सम्बद्ध योजना

इस योजना के अन्तर्गत, अनुश्जाति/अनुश्जनजाति के उम्मीदवारों को केन्द्र/राज्य सरकारों तथा सार्वजनिक उद्यमों के अन्तर्गत आने वाली विभिन्न सेवाओं में अपने प्रतिनिधित्व में सुधार जाने के जिए पूर्व परीक्षा भर्ती पशिक्षण केन्द्रों के माध्यम से शिक्षण प्रदान करने के लिए पिछली पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष तक किए गए कुल खर्च की प्रतिबद देनदारी के खर्च को परा करने के लिए राज्य सरकारों को 50 : 50 के आधार पर केन्द्रीय सहायना प्रदान की जानी है। संघ्रशासित क्षेत्रों के मामले में विश्वविद्यालयों तथा पारवेट शिक्षा संस्थानों को शत-प्रतिशत आधार पर केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है। अनुलजाति एवं अनुलजनजाति के उम्मीदवारों को परीक्षाओं के तीन संस्थ वर्गों के लिए पर्व परीक्षा शिक्षण प्रदान किया जाता है। ये सेवाएं हैं-केन्द्रीय सिविल सेवाएं चिकित्सा एवं अभियांत्रिको तथा अन्य सेवा वरीक्षाएं जिनमें राज्य सिविल वरीक्षाएं भी शामिल हैं। इस योजना में ब्राजावास में रहने वाले ब्राजों को 400/- रुपए प्रतिमाह नथा दिवा छात्रों के 100 रु० प्रतिमाह विका प्रदान की जाती है। इस योजना से प्रतिवर्ष लगभग 11(XX) छात्र लामान्यित होते हैं। इस समय 136 केन्द्रों में पूर्व परीक्षा शिक्षण प्रदान **किया** जाता है। वर्ष 1994-95 के दौरान 2.00 करोड रू० का कल आबंटन किया गया। वर्ष 1995-96 के लिए 3,00 करोड़ 50 का बजट आबंटन रखा गया है।

VII. अनुरुजाति/अनुरुजनजानि के खात्रों की योग्यता को बढाना:

इस याजना के अंतर्गत, अनः जाति/अनः जनजाति के छत्रों को उपचारी तथा विशिष्ट प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए राज्य सरकारों/संघशासित क्षेत्रीं को शत-प्रतिशत आधार पर केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) ने इस योजना को वर्ष 1987-88 में आरम्भ किया था। वर्ष 1993-94 के मध्य में इस योजना को कल्याण नंत्रालय को सौंपा गया था। इस योजना का उद्देश्य नवीं से बारहवीं कक्षा में पदने वाले अनुवजाति/अनुवजनजाति के छात्रों को उपचारात्मक तथा विशेष शिक्षा प्रदान करके उनकी सहायता करना है ताकि वे अपनी सामाजिक तथा शैक्षिक कमियों को सुधार सकें तथा मेडिकल एवं इंजीनियरिंग जैसे व्यावसायिक पाठयक्रमों में अपने प्रवेश को सकर बना सकें क्योंकि इन पाठयक्रमां में दाम्बला प्रतियोगी परीक्षाओं पर आधारित होता है। केन्द्र सरकार इस योजना का शत-प्रतिशत वित्तपोषण करती है। वर्ष 1994-95 में, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उडीसा, राजस्थान, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल इन 11 राज्यों ने इस योजना के अन्तर्गत अनुदान प्राप्त किया। इन 11 राज्यों में अन्वजाति/अन्वजनजाति के 2336 छात्रों को लामान्वित करने के लिए उस वर्ष 1.00 करोड़ रु० की कुल राशि जारी की गई। चालु वित्तीय वर्ष (1995-96) के लिए भी 1.00 करोड़ रु० का बजट प्रावधान है।

VIII. अनु जनजातियों के कल्याण के लिए स्वैच्छिक संगठतों को सहायता

भारत सरकार अनु० जनजातियों के कल्याण में संलग्न स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान प्रदान करती है। अनुसूचित जनजातियों के प्रत्यक्ष हित (लाम) के लिए गैर सरकारी संगठनों को सामान्यत: योजना जागत का 90% माग अनुदान सहायता दी जाती है। स्वैच्छिक संगठनों दारा संचालित योजनाओं में आश्रम विद्यालयों, छात्रावासों, चल चिकित्सा

यूनिटों, डिस्पैन्सिरयों. श्रव्य-दृश्य यूनिटों, पुस्तकालयों, व्यावसायिक केन्द्रों, शिशु गृहों तथा बालवाड़ियों का संचालन शामिल है। वर्ष 1994-95 के तौरान 79 गैर सरकारी संगठनों को 4.96 करोड़ रूपए का अनुवान दिया गया।

IX. अनुस्चित जातियों के लिए अनुसंघान तथा प्रशिक्षण योजना

अनुसंघान तथा प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत, अनुसूचित जातियों के विकास के लिए कार्यात्मक अनुसंघान एवं मूल्यांकन अध्ययन आयोजित करने के लिए विश्वविद्यालयों/संगठनों/सामाजिक विज्ञान अनुसंघान मंस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 1994-95 के दौरान, इस योजना के अन्तर्गत, 39 लाख रुपए का बजट प्रावधान रखा गया था। अनुसूचित जातियों के विकास के लिए 23 अनुसंघान तथा मूल्यांकन अध्ययन, 10 सेमिनार तथा 3 प्रशिक्षण पाठयक्रम आयोजित करने के लिए वितीय सहायता प्रदान की गई।

X. जनजातीय उप-योजना क्षेत्रों में आभ्रम स्कूल

जनजातीय उपयोजना क्षेत्रों में आग्रम स्कूलों की स्थापना की योजना वर्ष 1990-91 में आरम्भ की गई। इस योजना का मुख्य उदेश्य अनुमृचित जनजाति के छात्रों को वातावरण निर्माण संबंधी शिक्षण प्रदान करना तथा ग्राथमिक. मिडिल तथा माध्यमिक स्तरों पर पदाई बीच में छोड़कर जाने वाले छात्रों की संख्या कम करना है। इस योजना के अन्तर्गत आग्रम विद्यालय भवनों, छात्रावासों तथा स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण के लिए 50:50 के जाधार पर राज्य सरकारों को वितीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना में प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक स्तर की शिक्षा ग्रामित है।

वर्ष 1994-95 के दौरान, 18 आग्रम विद्यालयों के निर्माण के लिए राज्यों को 2.50 करोड़ रू० की राशि प्रदान की गई।

XI. शोध तथा प्रशिक्षण: डाक्टोरल तथा पोस्ट डाक्टोरल फैलोशिय प्रदान करना

शोघ तथा प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत. कल्याण मंत्रालय विश्वविद्यालयों में पंजीकृत तथा जनजातीय समस्याओं पर कार्य करने वाले क्षात्रों/विद्यानों को शत-प्रतिशत आधार पर शोघ फैलोशिप अनुदान प्रदान कर रहा है। वर्ष 1994-95 के वौरान, इस योजना के अन्तर्गत, 18 डाक्टोरल तथा । पोस्ट डाक्टोरल फैलोशिप प्रदान की गई।

XII. कम साक्षरता वाले क्षेत्रों में अनुमृचित जनजाति की लड़कियों के लिए शैक्षिक परिसर

कम साक्षरता वाले क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति की लड़िकयों के लिए श्रीक्षिक परिसर योजना वर्ष 1993-94 में आरम्म की गई तथा इसे सम्बद्ध राज्य सरकार की सहायता से गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है। इस योजना में उन आठ राज्यों, जिनमें वर्ष 1981 की जेनाणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति की महिलाओं की साक्षरता दर 2% से कम थी, के 48 जिलों को शामिल किया गया है। इस योजना में आदिम जनजातीय वर्गों, जिनमें महिला साक्षरता दर बहुत कम होती है, की

लड़िकयों को भी शामिल किया गया है, कल्याण मंत्रालय शैक्षिक परिसरों की स्यापना के लिए शत-प्रतिशत लागत प्रदान करता है तथा राज्य सरकार का कान, विश्वस्त तथा इच्छुक गैर सरकारी संगठनों का पता लगाना तथा परिसरों के लिए मुफ्त जमीन प्रदान करना है। ये श्रीक्षक परिसर, जनजातीय लड़िकयों की पांचवीं कक्षा के स्तर तक की शिक्षा तथा काप्य-/व्यावसायिक शिक्षा में प्रशिक्षण के लिए बनाए गए हैं। एक परिसर में पहली से पांचवीं कक्षा में पढ़ने वाली 50 लड़िकयों का प्रावधान रखा गया है। सहवासियों के लिए मोजन तथा रहने की मुफ्त व्यवस्था है। इस योजना में प्रतिवर्ध वर्षी के हो सीटों की आपूर्ति, बच्चों के लिए पक्षीय चिकित्सा जांच तथा सार्यकाल में लड़िकयों के जिममावकों के लिए प्रीय चिकित्सा जांच तथा सार्यकाल में कहि के अमिमावकों के लिए प्रीय चिकित्सा का प्रावधान है। अपनी पुत्रियों के इन आवासीय विद्यालय में भेजन के लिए अमिमावकों के प्रतिमाह 30/- ठक वो प्राचाहन दिया जाता है। वर्ष 1994-95 के दौरान 26 नए श्रीक्षक परिसर स्थापित करने तथा 16 शिक्षक परिसरों को जारी रखने के लिए गैर सरकारी संगठनों को 1.97 करोड़ रूठ की राश्चि प्रदान की गई।

XIII. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट घटक योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता

विशिष्ट घटक योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता की योजना, केन्द्रीय योजना है। जिसमें अनुमृचित जातियों के आर्थिक विकास के लिए विशिष्ट घटक योजना प्रतिपादित करने वाले 24 राज्यों (संघशासित क्षेत्रों को प्रदान की गई। विशेष केन्द्रीय सहायता को राज्यों (संघशासित क्षेत्रों की विशिष्ट घटक योजना के साथ प्रयुक्त किया जाना चाहिए। इस योजना को योजनाबद नरीके से तैयार नहीं किया है।

पूर्वोक्त दिशा निर्देशों के विस्तार में विशेष केन्द्रीय महायता को उन बताकों, जिनमें अनुसूचित जाति की 50 प्रतिशत अयवा इससे अधिक अनसंख्या रहती हो, में बुनियादी विकास कार्यक्रमों के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है, अशर्ते कि राज्य/संघ्यासित क्षेत्र, विशिष्ट घटक योजना के बार्यटन को इस तरीके के प्रयुक्त करें कि अनुसूचित जातियों के विकास के अधिकाधिक प्रयासों को प्रोत्साहन मिलें। विशेष केन्द्रीय सहायता को निम्निणित्तित के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है:—

- (क) जिन क्षेत्रों में साक्षरता स्तर काफी कम है, उनमें आवासीय स्कूलों की स्थापना तथा संचालन, तथा
- (ख) अनुसूचित जातियों के मौजूदा स्कूलों/खात्रावासों की मरम्मत तथा समुचित रखरखाव।

विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत वर्ष 1995-96 के लिए बजट आबंटन 275.00 करोड़ रू० है।

ग अन्य विभाग

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, श्रम मंत्रालय, कल्याण मंत्रालय आदि केन्द्रीय मंत्रालय अपने विशेष क्षेत्रों में उच्च शिक्षा से सम्बन्ध रखते हैं। अपने विशिष्ट क्षेत्रों में ये मंत्रालय वाखिले, खात्रपृत्तियों आदि के मामले में समकक्ष सविधाएं प्रदान करते हैं।

घ. राज्य बरकारें

राज्य स्तर पर, अनुसूचित जाति तथा अनु0 जनजातियों के लिए शिक्षा, हरिजन कल्याण, जनजातीय कल्याण एवं समाज कल्याण विमागों के बौक्षिक कार्यक्रम हैं। उनके गतिविधियों का कार्य क्षेत्र, एक राज्य से इसरे राज्य में भिन्न-भिन्न है। तथापि, शैक्षिक संस्थानों की स्थापना, विद्यालयों का निरीक्षण, पाठ्यक्रम नैयार करना तथा परीक्षाएं अयोजित करना, आदि कार्य करना सामान्यत: शिक्षा विभाग के अधिकार क्षेत्र में अते हैं। जबकि अनुस्चित जातियों एवं अनुस्चित जनजातियों के लिए छात्रवृत्तियां, मुफ्त वर्दी, आवासीय स्विचाएं प्रदान करने जैसी प्रोत्साहन योजनाएं, राज्य कल्याण विमागों द्वारा आरम्म की जा रहीं हैं।



अनुस्चित जाति तथा अनुस्चित जन जाति की जनसंख्या—जनगणना-1991

		<u> </u>	सृचित जाति जनः	पंख्या	अनु स् चित	ात जनजाति जनसंख्या		
क्रम संख्या	राज्य/संबर्शासित क्षेत्र —	पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	中報 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	आंध्र प्रदेश	5379654	5212412	10592066	2142817	2056664	4199 481	
2.	अरूणाचल प्रदेश	2491	1561	4052	275397	274954	550351	
3.	असम	864617	794795	1659412	1461560	1412881	2874441	
4.	बिहार	6569360	6002340	12571700	3357563	3259351	6616914	
5.	गोवा	12389	11975	24364	199	177	376	
ė.	ग्जरान	1589686	1470672	3060358	3131947	3029828	6161775	
7.	हरियाणा	1747821	1503112	3250933	_	_	_	
8.	हिमाचल प्रदेश	666055	644241	1310296	110240	108109	218349	
۹.	जम्म और कश्मीर				-	_	_	
13.	कनाटक	3756069	3613210	7369279	976744	938947	1915691	
11.	केरल	1422614	1463908	2586522	160812	160155	320967	
12.	मध्य प्रदेश	5027806	4598873	9526679	7758174	7640860	15399034	
13	महागएट	4505375	4252467	8757842	3717783	3600498	7318281	
14	म "णप्र	18806	18299	37105	322720	309453	632173	
15.	मं चालय	4981	4291	9072	760234	757693	1517927	
iė.	मि जोरम	597	94	691	329819	323746	653565	
17.	नामानी ड	_	_	_	545156	515666	1060823	
18.	्र ा ग्रा	2596464	2532850	5129314	3512891	3519323	7032214	
184	यं तस्य	3065671	2676857	5742528	_	_	_	
22.	म सम्भान	4007220	3600600	7607820	2837014	2637867	547488	
21.	'ग्रां म्हम	12424	11660	24084	47504	43397	9090	
22.	राधनसम्ह	5414599	5297667	10712266	293012	281182	5741 9 4	
23.	time	231516	219600	451116	434225	419120	85334:	
24	इनः प्रदेश	15599178	13677277	29276455	150420	137481	28790	
25	पॉण्चम बंगाल	8326832	7753779	16080611	1938955	1869805	38087 6 0	
20	अंद्रमान, निकायार द्वीप समृह			_	13750	13020	26770	
27	भगडोगम्	58554	47423	105977	_		_	
28.	वादग और नगर तवानी	1418	1312	2730	54102	55278	109386	
29.	दमन और धाव	1882	2009	:801	6073	5651	11724	
30	दिल्ली	978690	816146	1794836	_		_	
31.	लक्षद्वीप	_	_	_	24160	24003	4816.	
32.	पांडिचेंग	66191	65087	131278	_	_	-	
	भारत	71928960	66294317	138223277	34363271	33395109	67758380	

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की साक्षरता दर—1991

			अनुसूचित जा साक्षरता			वत जनजातियों क ी साक्षरता दर	1
		कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला
1.	आंध्र प्रदेश	31.59	41.88	20.92	17.16	25.25	8.68
2.	अरूणाचल प्रदेश	57.27	66.25	41.42	34.45	44.00	24.94
3.	असम	53.94	63.88	42.99	49.16	58.93	38.98
4.	बिहार	19.49	30.64	7.07	26.78	38.40	14.75
5.	गोवा	58.73	69.55	47.51	42.91	54.43	29.01
6.	गुजरात	61.07	75.47	45.54	36.45	48.25	24.20
7.	हरियाणा	39.22	52.06	24.15		nare.	****
8.	हिमाचल प्रदेश	53.20	64.98	41.02	47.09	62.74	31.18
9.	कर्नाटक	38.06	49.69	25.95	36.01	47.95	23.57
10.	केरल	79.66	85.22	74.31	57.22	63.38	51.07
11.	मध्य प्रदेश	35.08	50.51	18.11	21.54	32.16	10.73
12.	महाराष्ट्	56.46	70.45	41.59	36.79	49.09	24 03
	मणिप्र	56.44	65.28	47.41	53.63	62 39	44.48
	मेघालय	44.27	54.56	31.19	46.71	49.78	43.63
15.	मिजोरम	77.92	77.54	81.25	82.71	86 66	78.70
16.	नागालैंड		Name of the last o		60.59	66.27	54.51
17.	उडोसा	36.78	52.42	20.74	22.31	34 44	10.21
	पंजा ब	41.09	49.82	31.03			
	राजस्थान	26.29	42.38	8.31	19.44	33.29	4.42
	सिक्किम	51.03	58.69	42.77	59 () 1	66.80	50.37
	तमिलनाड्	46.74	58.36	34.89	27.89	35.25	20.23
	त्रिपुरा	56.66	67.25	45.45	40.37	52.88	27.34
	उत्तर प्रदेश	26.85	40.80	10.69	35.70	49,95	19.86
	पश्चिम बंगाल	42.21	54.55	28.87	27.78	40.07	14 98
	अंडमान, निकोबार द्वीप समृह				56.62	64.16	48.74
	चण्डीगढ	55.44	64.74	43.54			
	दादरा और नगर हवेली	77.64	88.03	66.61	28.21	40.75	15 94
	दमन और दीव	79.18	91.85	67.62	52.91	63.58	41 49
	दिल्ली	57.60	68.77	43.82			
	लक्षद्वीप				80.58	89.50	71.72
	पांडिचेरी	56.26	66.10	46.28			
	भारत*	37,41%	49.91%	23.76° o	29.60° o	40.65%	18 19%

[🔭] जम्मू और कश्मीर के आंकड़े सिम्मिलित नहीं हैं क्यों कि वहां 1991 में जनगणना नहीं हो पायो थी।

श्रोतः भारतं की जनगणना 1991: अनुमृचितं जातियों और जनजातियों के संघोय प्रार्थीमक आंकड़े। भारतं का महालेखाकार और जनगणना आयुक्त।

अनुवंध—III विभिन्न स्तरों पर अनुस्वित जाति तथा अनुस्वित वनजातियों का नामांकन—1993-94

		अनुसूचित जार्	ते		अनुसृचित जनजाति		
	लइके	लड़कियाँ	जोड़	लड़के	लड़कियाँ	बोड़	
1. पूर्व प्राथमिक	105347	86324	191671	195036	17 541 5	370451	
	(9.95)	(8.16)	(9.88)	(18.43)	(19.87)	(19.09)	
2. प्राथमिक	10411738	7169052	175807 90	5153555	3441127	8594682	
	(16.85)	(15.45)	(16.25)	(8.34)	(7.42)	(7.94)	
3. मिडिल	3565766	2014291	5580057	1424374	769760	2194134	
	(14.73)	(12.83)	(13.98)	(5.88)	(4.90)	(5.50)	
4. डाई स्कूल	1402370	6111 54	2013524	496905	240005	736910	
	(13.78)	(10.91)	(12.77)	(4.88)	(4.28)	(4.69)	
 उच्चतर माध्यमिक/इंटर कालेज	578871	215219	794090	185557	74885	260442	
इत्यादि	(11.36)	(8.71)	(10.50)	(3.64)	(3.03)	(3.44)	
6. बी० ए०/(जानस्)	141936	52147	194083	57218	26267	83485	
	(12.22)	(6.88)	(10.01)	(4.93)	(3.45)	(4.34)	
7. बीठ कॉम/(जानमी)	47019	13878	60897	11181	3157	14338	
	(6.29)	(5.00)	(5.94)	(1.50)	(1.1 4)	(1.40)	
8. बां०एस०सी०/(जानसं)	41267	17064	58331	8180	25 ⁷ 9	10759	
	(7.65)	(6.47)	(7.26)	(1.52)	(0.98)	(1.34)	
9. শীত হাত/শীত শ্রত	6567	2789	9356	2144	806	2950	
	(11.62)	(6.13)	(9.18)	(3.79)	(1.77)	(2.89)	
 बीठ ई०/बीठएस०सीठ	14580	2373	16953	3783	336	4119	
(इजीनियरिंग)	(6.08)	(7.89)	(6.28)	(1.58)	(1.12)	(1.52	
II एम ाना ज्याला एस ल	4422	2726	7148	1438	1272	2710	
	(7.90)	(8.46)	(8.10)	(2.57)	(3.95)	(3.07	
12. что чо	20895	4813	25708	4399	1620	6019	
	(15.70)	(5. 46)	(12.06)	(3.31)	(1.84)	(2.82)	
13. एम० कॉम	5400	1072	6472	1259	203	1462	
	(9.13)	(6.3 6)	(8.51)	(2.13)	(1.21)	(1.92	
14. एम० एस० सी०	2956	997	3953	664	251	815	
	(5.91)	(3.93)	(5.24)	(1.33)	(0.99)	(1.08	
5. एम० फिल०/पी०एच०डी०	963	251	1214	188	93	281	
	(4.67)	(2.48)	(3.95)	(0.91)	(0.92)	(0.92	
16. शिक्षक प्रशिक्षण स्कृल	8449	7241	15690	6372	4195	1056	
	(13.63)	(10.61)	(12.05)	(10.28)	(6.15)	(8.12	
17. पॉलिटेक्नीक संस्थान	29213	4832	34045	8864	1065	9929	
	(10.47)	(10.02)	(10.41)	(3.18)	(2.21)	(3.04	
18. त0 औठ कला शिल्प स्कूल	48576	7544	56120	15760	2309	18069	
	(10.48)	(11.89)	(10.65)	(3.40)	(3.64)	(3.43	

टिप्पण्डी: alo জাo/alo জo জানিয়া জे জুল নামাকন की प्रतिशतता कोएउक में दर्शाई गई है। यह জুল जनसंख्या alo জাo/alo জাo জা জনसंख्या के प्रतिश्चत 16.33 तथा 8.01 है।

स्कूल खोड़ जाने वाले अनुसूचित जाति के खात्रों की दर -1989-90

राज्य/संघशासित क्षेत्र	/संघशासित क्षेत्र	प्रा	इमरी स्तर		मिडि	न स्तर		माध्यमिक स्तर				
		लड़के	लड़िकयां	जोड़	लड़के	लड़िकयां	जोड़	लड़के	लड़िकयां	जोड़		
٦.	आन्ध्र प्रदेश [®]	60.53	65.83	62.80	77.41	85.44	80.85	84.17	88.74	86.15		
2.	अरुणाचल प्रदेश	_	_	_	_	_	_		_			
3.	असम	46.88	55.89	50.80	64.91	63.47	64.30	62.54	62.02	62.33		
4.	बिहार	67.69	73.50	69.33	83.37	89.79	85.04	87.98	94.20	89.50		
5.	गोवा	39.27	32.06	36.02	55.52	65.68	60.28	79.26	85.57	82.27		
6.	गुजरात	24.95	45.55	34.13	50.40	70.34	59.11	66.50	79.78	72.21		
7.	हरियाणा	33.90	43.18	38.00	59.19	75.36	65.71	64.64	80.72	69.84		
8.	हिमाचल प्रदेश	36.29	36.50	36.39	32.27	41.88	36.44	67.02	76.81	71.12		
9.	जम्मू और कश्मीर	39.27	30.39	35.84	50.11	52.73	51.10	77.86	82.32	79.52		
	कर्नाटक	51.05	59.59	54.90	62.11	73.77	67.08	73.63	84.60	78.45		
11.	केरल	0	1.78	0.50	19.04	15.60	17.37	54.47	47.76	51.20		
12.	मध्य प्रदेश	36.31	52.37	42.41	62.34	79.40	67.78	75.11	86.91	78.48		
13.	महाराष्ट्र	38.54	51.58	44.60	52.90	69.77	60.54	67.91	81.16	73.83		
14.	मणिपुर	79.86	82.21	81.03	84.89	86.07	85.48	82.14	82.69	82.42		
	में घाल य	33.13	41.88	37.46	27.86	51.85	39.64	34.62	66.39	50.00		
16.	मिजोरम	_	_	_	_	_	_					
17.	नागालैण्ड		_	_	_	_		_				
18.	उड़ीसा	55.16	59.22	56.77	75.97	83.19	78.76	77.86	86.42	81.22		
	यंजा ब	36.58	41.59	38.79	63.36	70.56	66.52	78.88	85.96	82.13		
	राजस्थान	60.42	74.37	63.89	69.53	83.53	72.18	80.82	92.39	82.96		
	सिक्किम	70.00	67.85	69.04	84.96	83.67	84.37	91.62	93.60	92.51		
	तमिलनाडु	22.56	29.68	25.92	51.04	53.14	51.97	74.75	82.69	78.31		
	त्रिपुरा	58.21	63.09	60.47	75.87	81.84	78.60	86.88	90.20	88.39		
	्यः उत्तर प्रदेश	32.89	51.69	38.86	57.92	69.52	60.87	66.97	84.97	71.57		
	पश्चिम बंगाल $^{@}$	58.54	66.71	61.92	74.18	84.88	79.02	89.74	90.12	89.88		
	अंश्वा निश्वी समृह	_	_		_		_	_	_	_		
	चण्डीगढ	0	0	0	0	0	0	27.17	14.23	21.03		
	*दादरा और न०ह०	18.60	36.96	28.09	0	0	0	45.28	70.27	55.56		
	दमन और दीव	_	_	_	_	_	_	_	_	_		
	दिल्ली	33.74	35.74	34.63	47.68	58.61	52.79	54.06	74.25	63.71		
	लक्षद्वीप -	_		_	_	_	_	_	_	_		
	पांडिचेरी	0	0	0	0	11.96	5.45	69.92	75.32	72.42		
19	 गरत	45.93	53.74	49.03	64.29	73.10	67.62	76.61	84.20	79.42		

[@] ये खांकड़े वर्ष 1988-89 से सम्बन्धित है।

^{*}गोवा में शामिल किया गया।

स्कूल छोड़ जाने वाले अनुसूचित जनजाति के छात्रों की दर वर्ष -1989-90

		प्राह	मरी स्तर ——		मिडिल	त स्तर			माध्यमिक स्त	τ
		लड़के	लड़िकयां	जोड़	लड़के	लड़कियां	जोड़	लड़के	लड़िकयां	जोड़
?	. अन्ध प्रदेश ^{(त}	65.24	70.54	67.22	84.16	89.92	86.28	89.59	92.95	90.84
2.	अरुणाचल प्रदेश	63.47	59.43	61.98	78.52	77.90	78.30	81.97	88.10	84.06
3.	असम	65.15	65.87	65.46	71.78	75.67	73.44	70.80	75.82	72.93
4.	बिहार	70.78	70.93	70.83	85.67	87.57	86.33	90.89	92.72	91.51
5.	गोत्रा	28.99	19.80	24 .72	63.50	71.88	67.36	73.58	87.32	79.57
6.	गुजरात	54.03	66.62	59.48	76.17	82.62	78.88	85.34	89.14	86.90
7.	हरियाणा	_	_	_	_		_	_	_	_
8.	हिमाचल प्रदेश	30.59	34.53	32.23	36.58	45.89	40.03	67.93	70.41	68.79
9.	जम्म और कश्मीर	_	-	_	_	_	_	_	_	_
10.	कर्नाटक -	47.97	50.69	49.13	56.82	66.68	61.09	72.70	77.23	74.46
11.	केरल	18.88	15.88	17.44	36.02	35.30	35.68	70.14	65.86	68.12
12.	मध्य प्रदेश	48.38	60.36	52.82	75.57	85.14	78.61	83.74	91.81	86.14
13.	महाराष्ट्	56 99	66.52	61.07	73.14	82.44	76.98	81.56	89.50	84.74
14	मणिप्र	77.54	78.43	77.95	84.76	85.79	85.23	85.44	87.24	86.26
15.	मेघालय	40.07	55.34	47.24	72.78	72.98	72.87	91.47	93.14	92.28
16	मिशारम	49.56	49.20	49.39	61.99	59.78	60.92	52.47	52.63	52.55
17.	नागानीण्ड	34 75	43.54	39.00	70.71	64.85	68.15	75.97	73.87	75.10
	उईास	77.66	78.66	77.98	84.33	86.92	85.26	87.49	92.84	89.38
	पंजाब	_		_	_	_	_	_	_	_
20	राजस्थान	69.76	83.15	73.08	74.74	90.17	77.65	84.93	94.30	86.45
21.	নিবিক্স	62.87	50.46	57.73	71.26	65.41	68.70	85.52	86.81	86.07
22.	र्रामलनार्	38.35	49.10	43.29	57.65	66.11	61.31	57.52	60.30	58.60
23.	त्रिपुरा	71.97	76.53	73.91	85.55	88.19	86.64	90.47	93.24	91.56
	उत्तर प्रदेश	17.22	59 64	34.11	47.73	74.11	55.59	33.49	78.84	46.31
25.	पश्चिम बंगाल ।	64.45	69.96	66.38	81.42	88.50	83.87	92.51	92.88	92.62
26.	वं और निंदीं स्व	5.73	19.77	12.36	49.44	47.88	48.73	55.23	62.58	58.57
27.	चर्रागढ	_		_		_	_	_	_	_
	दादरा और न०ह०	37.97	64.90	50.34	68.29	77.04	71.75	84.32	89.28	86.45
	*दमन और दीव	_	_	_	_	_	_	_	_	
	दिजनी	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	लक्षदीप	0	0	0	41.03	50.62	45.53	75.15	81.85	78.34
	पांडिचेरी	_	_	_	_	_	_	_	_	_
	भारत	61.86	66.98	63.81	77.42	82.67	79.35	84.83	88.90	86.28

 a^{i} आंकड़े वर्ष 1988-89 से सम्बन्धित हैं।

^{*}गोवा में शामिल किया गया।

31-3-94 तक नवोदय विद्यालयों में नामांकित किए गए सात्र (कहा-VI-VIII)

ज ावचा लय		कक्षा-VI		8	क्ष्ता-VII		7	हसा-VIII	
का नाम	ঐ ০ অ 1০	গ্রওবনও जाति	ओड़	ঐ ০জা০	ব্য ০অ০ জানি	जोइ	अ ०जा०	अ०जन० जाति	जोड़
अण्डमान तथा नि०	1	8	61	0	0	38	0	l	24
आन्ध्र प्रदेश	322	164	1659	327	136	1596	321	133	1560
ब्ररुणाचल प्रदेश	6	201	294	1	143	217	9	115	193
असम	17	30	47	9	39	48	0	0	0
बिहार	439	231	1983	465	227	2072	453	238	2001
चण्डीगद	32	0	74	25	0	68	7	0	36
दादरा और न ः ह0	1	18	25	2	32	42	1	12	15
दमन और दीव	6	7	93	8	2	41	1	0	13
दिल्ली	36	1	152	27	3	127	27	0	121
गोवा	3	1	97	0	0	30	6	3	42
पुजरात	150	74	660	115	72	530	78	28	425
हरियाणा	198	1	661	251	6	783	219	9	646
हिमाचल प्रदेश	210	122	685	231	83	662	164	76	549
जम्मू और कश्मीर	127	136	686	103	131	590	98	115	617
কর্না ত্র ক	260	87	1342	170	72	1207	130	24	1055
केरल	182	25	878	181	14	840	164	24	794
लक्षदीप	0	20	21	0	11	12	0	10	12
मध्य प्रदेश	581	381	2630	400	239	2176	257	115	1500
महाराष्ट्	381	190	1557	309	180	1360	287	161	1121
मणिपुर	71	304	603	79	206	496	52	191	421
मेघालय	19	183	283	27	177	276	11	81	135
मिजोरम	1	175	181	0	97	98	0	54	55
नागालैण्ड	4	90	94	1	56	57	11	38	54
उड़ीस।	182	247	848	167	222	780	175	219	765
गं डिचेरी	35	0	103	31	()	133	15	0	90
पंजा ब	278	1	699	246	9	586	118	0	434
गजस्थान	327	209	1412	316	159	1337	200	112	1122
सिक्किम	2	83	142	4	35	85	0	13	13
त्रिपुरा	43	30	141	39	27	134	45	32	113
उत्तर प्रदेश	932	64	3176	684	30	2631	467	18	2204
कल जोड	4855	3083	21287	4218	2408	19052	3316	1822	16130

स्रोत: नवोदय विद्यालय समिति की वर्ष 1993-94 की वार्षिक रिपोर्ट

31-3-94 तक नवोदय विद्यालयों में नामांकन (कक्षा 9-12)

ग ०न ० वि०	ō	हसा-9		क	क्षा-10		a	हसा - 1 1		कक्षा-12			कुल जोड़
हानाम	স্থ া তনাত	अ ० ज० जा०	जोड़	ৰ ০জা০	ক্তাত নাত	जोड़	ৰ ৩ জাও	# 0ज0 जा0	जोड़	ৰ ০ ল ০ :	1 0ज0 जा0	जोड़	(VI- XII)
अण्डमान तथा नि०	9	0	50	26	30	100	0	2	17	0	4	48	347
आन्ध्र प्रदेश	312	83	1357	309	92	1358	183	41	862	116	12	741	9133
अरुणाचल प्रदेश	14	15	109	14	51	125	1	65	76	1	54	67	108
असम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
बिहार	355	107	1001	325	152	1548	177	160	1073	136	135	1014	1141
वण्हीगद	6	l	41	14	0	49	2	0	17	7	0	18	30
वदरा और न०६०	3	1	18	9	6	27	0	0	0	4	4	15	14
दमन और दीप	7	1	13	17	1	45	0	0	0	0	0	0	23
दिल्ली	15	0	55	14	0	56	5	0	28	0	0	0	53
गोवा	15	2	85	18	0	92	2	0	30	6	4	22	39
गुजरात	48	43	287	60	67	321	31	36	174	22	52	149	254
हरियाणा	164	18	505	151	15	538	105	3	352	54	1	225	37
हिमाचल प्रदेश	132	44	194	128	74	440	106	16	278	127	59	368	33
जम्मू और कश्मीर	71	118	527	79	66	402	10	0	72	26	3	162	30.
कर्नाटक	141	44	1002	154	50	899	117	44	732	144	37	662	689
केरल	146	24	663	132	29	694	116	14	621	49	5	389	48
लक्षडीप	2	7	9	0	17	24	1	8	14	0	0	0	
मध्य प्रदेश	220	108	1296	300	162	1410	119	65	626	130	111	743	103
महाराष्ट्र	218	109	953	240	148	1018	93	55	326	123	65	432	67
मणिपुर	56	129	384	56	77	302	. 2	38	113	1	9	52	23
मेघालय	24	20	83	17	15	52	: 2	10	61	2	10	23	9
मिजोरम	0	23	2.3	0	11	12		15	22	0	0	0	3
नागालैण्ड	8	8	19	0	0	0	. (0	0	0	0	0	2
उदीसा	165	178	208	144	174	766	95	92	428	96	109	512	48
पढिचेरी	21	0	119	29	11	144	9	0	49	32	0	141	7
पे जाब	89	1	341	112	1	389	71	8	232	50	0	170	28
राजस्थान	238	110	1017	7 257	136	1112	220) 99	839	140	85	626	74
सिकिकम	1	2	23	3 4	39	74	() 44	69	0	0	0	4
त्रिपुरा	23	13	69	9 17	14	69) (5 10	23	0	0	0	5
उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश	356			7 409	77	1797	194	2	919	134	3	731	131
कुल ओइ	2868	1387	1360	7 3044	1515	1386	166	7 836	8053	1400	762	7310	993

स्रोत: नवोदय विद्यालय समिति की वर्ष 1993-94 की वार्षिक रिपोर्ट

वर्ष 1994-95 के दौरान प्रदत्त एन०टी०एस० खात्रवृत्तियों की संख्या

क्र०सं० राज्य/संघशासित क्षेत्र	प्रवत खात्रवृत्तियो की संख्या (सामान्य)	ख०जा०/ख०ज० जातियों को प्रदत्त आरक्षित छात्रवृत्तियां
1. खान्य प्रदेश	31	2
2. अरुणाचल प्रदेश	_	
3. खसम	5	_
4. बिहार	32	4
5. गोवा	-	_
6. गुजरात	2	1
7. हरियाणा	16	_
8. हिमाचल प्रदेश	4	_
9. जम्मू और कश्मीर	1	_
10. कर्नाटक	57	8
11. केरल	50	4
12. मध्य प्रदेश	32	5
13. महाराष्ट्र	152	9
14. मणिपुर	-	2
15. मेघालय	1	4
16. मिजोरम	_	-
17. नागालैण्ड	_	_
18. उड़ीसा	25	5
19. पंजाब	35	3
20. राजस्यान	47	4
21. सि क्कि म	1	
22. तमिलनाडु	54	4
23. त्रिपुरा	_	1
24. उत्तर प्रदेश	68	3
25. पश्चिम बंगाल	22	9
26. अ०नि०दीप समूह	_	_
27. चण्डीगढ़	6	1
28. दादरा नगर हवेली	-	_
29. दिक्ली	38	_
30. दमन एवं दीय	_	_
31. लक्षद्वीप	_	_
32. पंडिचेरी	1	_
जोड़	680	70

स्रोत : रा०शै०अनु० तथा प्र० परिषद की वार्षिक रिपोर्ट

अनुबन्ध-VIII

वर्ष 1994-95 के दौरान डी०एम०एस० में अ०जा०/अ०ज०जातियों का नामांकन

स्तर/कक्षाएं	अ	जमेर		मुव	नेश्वर		ŧ	सूर		ŧ	ोपाल	
	अ ०जा०-	- 310ज0 जा0	जोड़	অ ০জা০	রতের ০ জাত	जोड़	ম ৩ বা ৩	গ্ৰতন্ত নাত	जोड़	স্তা ত	ৰতেৱত ব্যাত	जोड़
Ī.	5	5	31	13	4	70	13	6	67	10	8	73
11.	7	1	37	7	6	68	13	4	72	11	7	24
Ш.	4	2	46	10	7	80	13	6	74	10	4	78
IV.	6	3	47	11	7	89	9	4	76	7	7	82
V.	3	1	47	15	10	126	12	_	89	11	9	88
VI.	5	_	48	21	7	138	14	1	66	13	5	95
VII.	5	2	88	22	8	136	19	2	87	8	3	84
VIII.	6	_	72	19	6	117	15	2	73	11	5	80
tX.	6	ı	92	14	5	127	12	4	70	10	3	71
X.	7	2	117	12	2	126	3	2	61	12	4	72
XI.	4	_	95	8	1	100	6	1	74	6	1	67
XII.	1	-	88	6	3	150	3	_	48	5	3 ,	87
	59	17	808	158	66	1327	132	32	857	114	59	903

स्रोत : रा०गै० अनु० तथा प्र० परिषद की वार्षिक रिपोर्ट

वर्ष 1994-95 के दौरान पूर्व सेवा पाद्यकल क्षे**र**्डजी०सं०/क्षेठ्डजी०कालेज में अ०जा०/अ०ज०जा० के खात्रों का नामांकन

पाठ्यक्रम	क्षे०इज	ो०स० अजं	ोर	क्षेठहंजीठसंठ भुवनेश्वर			क्षे०इंजी	क्षं० मैसूर		क्षे ंड जी०सं० मोपाल		
	অ ০লা০	রতেরত বাত	जोड़	<i>ঝ</i> ০না ০	उ द्या उ ज्ञ	० जोइ	ন ত্তনাত	নাত নাত	ओड़	র ৩না৩	ন্ত্ৰত ভাতন্ত	जोड़
बी०एड० (विज्ञान)	23	3	84	15	8	₩ 100	_	_	_	11	4	62
बी०एड० (वाणिज्य)	8	_	22	4	2	20	_	_		11	5	43
बी०एड० (कृषि)	6	1	29	3.09.	_			-	_	_	_	-4
बी०एड० (इंजी०)	7	1	29	_	_	_	_	_		_	_	_
बी०एड० (डिन्दी)	9	2	39	_	_	_			~	_	-	_
बी ० एड० (उर्दू)	_	_	22	_	_	_	_	~	_	-	_	_
बींएड ०	46	9	265	13	7	87	29	9	221	30	3	248
(बी०एस०सी०)												
बी०एड० (बी०ए०)	_	_	_	9	8	66	18	8	127	30	6	189
बी०एड० (क ला)	_	_	_	9	5	60	_	_	_		_	
बी 0एड0	_	_	_	4	2	20	_	-			_	
(ৰা ০কাম ০)												
बी 0एड0	_	_	_	_	_	_	3	3	67	_	-	-
एम०एड०	2	_	15	3	2	19	3	2	25	3	1	24
रम०एस०सी०	_	_	_	2	1	19	_	_	_	_		-
(एल०एस०)एड०												
एम०एस०सी०एह०	_	_	_	-	_	-	11	_	107	_	_	
जोड़	101	16	505	59	35	391	64	22	547	85	. 19	566

स्रोत: राञी०अनु० एवं प्र०प्न० की वार्षिक रिपोर्ट